● वर्ष-3
● अंक-164
रायपुर, शनिवार
17 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› ऑफिस का पहला दिन ....

प्रदेश के स्कूलों में अब 'न्योता भोजन'

सामुदायिक भागीदारी से भोजन को अधिक पोषक बनाने की पहल

न्योता भोजन, स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदाय करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाईडलाईन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे 'न्योता भोजन' के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि तथा सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन, स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकेंगे। न्योता भोजन, स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह विद्यार्थियों को दिए जा रहे भोजन का पूरक होगा।

राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर से आज इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 'न्योता भोजन' के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के दिशा निर्देश के अध्याय 12 में 'तिथि-भोजन' के नाम से दिये गये हैं, इसका पालन करना भी सुनिश्चित करें।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि 'न्योता भोजन' की अवधारणा एक सामुदायिक

भागीदारी पर आधारित है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों/त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। ध्यान रहे न्योता भोजन शाला में दिये जाने वाले भोजन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किये जाने वाले भोजन का पूरक है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में न्योता भोजन की अवधारणा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभांवित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते है।

संभावित दाताओं की पहचान

समुदाय में ऐसे दान दाताओं की पहचान की जा सकती है जो रोटेशन में माह में कम से कम एक दिन शाला में 'न्योता भोजन' करा सके। दान दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें शाला की प्रार्थना सभा अथवा वार्षिक दिवस में सम्मानित किया जाए। भोजन दान की प्रकृति को महादान के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसमें पूरे विद्यालय अथवा किसी कक्षा विशेष के बच्चों को 'न्योता भोजन' कराया जाता है। 'न्योता भोजन' के दिन दान-दाता को शाला में आमंत्रित किया जाए। 'न्योता भोजन' की घोषणा प्रार्थना के दौरान की जाए। घोषणा में दान-दाता के नाम की भी घोषणा की जा सकती है अथवा उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ी में एम.ए. करने वाले की जल्द होगी भर्तियां

छत्तीसगढ़ी में एम.ए. करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए पीएससी व व्यापम के माध्यम से भर्तियां निकाली जाएगी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा पर स्नातक डिग्रीधारियों को नौकरी के अवसर मुहैय्या कराएगी। जिन नौजवानों ने छत्तीसगढ़ी में एमए पास किया है उन लोगों के सीजीपीएसी और व्यापम के जरिए करने भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी की बात की है उसके लिए कोई काम नहीं किया। शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में कई सालों से सहायक शिक्षकों शिक्षकों, लैक्चरर की पदोन्नति नहीं हुई है। जिस कारण उनमें असंतोष है साथ ही विभाग में बड़ी संख्या में पद भी रिक्त है। जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि, प्रमोशन की जितनी भी गतिविधियां है उनको अगले 6 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कई स्थानों पर स्कूल की इमारत या तो बहुत जर्जर हो चुकी है या इमारत ही नहीं है। ऐसे में अगले 5 सालों में जर्जर इमारत का पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा।

कांग्रेस बैंक अकाउंट पर रोक नहीं -आईटी विभाग

नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि, अब इस मामले में इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों ने रिएक्ट किया है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से 115 करोड़ रुपये की वसूली का जिक्र किया है। यह कार्रवाई 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये की आयकर डिमांड पर की गई है। अकाउंट फ्रीज के आरोपों पर आयकर विभाग ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि, विभाग ने ये भी बताया कि बैंक खातों की एक्टिविटी या ऑपरेशन पर कोई रोक नहीं है।

आयकर विभाग ने बताया क्यों की कार्रवाई

इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ साल 2018-19 के लिए 135 करोड़ रुपये का बकाया मांग लंबित है। इसका मूल्यांकन करने पर 103 करोड़ रुपये की डिमांड और 32 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। ऐसे में जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की गई। कांग्रेस से कुल मांग का 20 फीसदी भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी ओर से 78 लाख रुपये का भुगतान किया गया। सीआईटी(ए) और आईटीएटी के समक्ष अपील खारिज होने के बाद, आयकर विभाग ने बैंक खातों से पैसे निकालकर वसूली की है।

अजय माकन ने किया था ये दावा

आयकर विभाग के सूत्रों ने कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस दावे का भी खंडन किया कि बैंक अकाउंट का ऑपरेशन या एक्टिविटी रोकी गई। यह एक नियमित प्रक्रिया है और इससे पार्टी के खातों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। इससे पहले, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया था कि पार्टी के मुख्य बैंक खातों को कमजोर आधार पर फ्रीज कर दिया गया।

जिससे आगामी आम चुनावों से पहले उनकी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। अजय माकन ने कहा था कि भारतीय युवा कांग्रेस के खाते सहित चार मुख्य बैंक खातों को 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपये की आयकर मांग के कारण फ्रीज कर दिया गया था। अजय माकन ने इस कार्रवाई को पार्टी की ओर से आयकर रिटर्न कुछ दिनों की देरी से दाखिल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

किसानों के भारत बंद का रहा मिला-जुला असर

नई दिल्ली। किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान का देश में मिला-जुला असर देखने को मिला। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसान फिर एक बार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के सामने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों ने गुरूवार को सुबह छह बजे से शाम के चार बजे तक भारत बंद का एलान किया था। भारत बंद का आह्वान किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के बीच आया। किसानों के इस प्रदर्शन के कारण रेल यातायात बाधित हो रही है। करीबन छह ट्रेनों को लुधियाना-साहनेवाल-चंडीगढ़ रूट पर डायवर्ट कर दिया गया है। इस हड़ताल के दौरान परिवहन, कृषि गतिविधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, गांव की दुकानें और ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद रहे। भारत बंद के बीच पंजाब के जालंधर में टैक्सी और ऑटो यूनियन ने भी यातायात बंद रखने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि वे भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इस बंद का असर राजधानी दिल्ली में कम देखने को मिला, क्योंकि यहां 700 बाजार और औद्योगिक कारखाने खुले रहे। वहीं, इस आंदोलन का असर पंजाब में ज्यादा दिखा।

दिल्ली की सीमाओं पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब के कपूरथला में भारत बंद का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें बंद है। किसानों ने हाईवे पर भी जाम लगा दिया है। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर आज किसानों का भारत बंद रहा। जिसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, तो वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिक की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल के किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के चलते 70 साल के किसान की जान चली गई। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया था। यहीं किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसानों ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद किसान को राजपुरा अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक राजपुरा अस्पताल से किसान को पटियाला के गवर्नमेंट राजिंदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था।

प्रमुख समाचार

दिल्ली: पेंट फैक्टरी में आग, 11 की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में नरेला के पास अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रह हैं। गुरुवार शाम हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई और मजदूर फैक्ट्री में ही फंसे रह गए। लोगों का आरोप है कि आग लगते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई लेकिन वह काफी देर से पहुंचे। इस मामले में को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जांच के आदेश देने की बात कही है। मामला बढ़ने के बाद अब दमकल अधिकारियों ने मामले पर सफाई दी है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताााया कि इलाके के आसपास काफी जाम था जिसकी वजह से टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताााया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए लगाए गए बैरिकेड्स के कारण ट्रैफिक जाम लग गया था और इसी वजह से दमकल गाड़ियों को पहुंचने में देरी हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है।

मणिपुर में सुरक्षाबलों से भिड़े उपद्रवी; दो की मौत

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सुरक्षाबलों के साथ झड़प में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। चिराचांदपुर जिले में उपद्रवियों ने एसपी ऑफिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक लगभग 400 प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय को घेर लिया था। वे सभी एक हेड कॉन्स्टेबल सियामलालपॉल की बहाली की मांग कर रहे थे। बता दें कि यह पूरा मामला एक सेल्फी से जुड़ा हुआ था। यह पूरा मामला एक सेल्फी से जुड़ा हुआ है। 14 फरवरी को हेड कॉन्स्टेबल का एक सेल्फी वीडियो सामने आया था जिसमें वह हथियारबंद लोगों के साथ दिखाई दे रहा था। ये कुकी उग्रवादी थे। इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए हेडकॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया। इसके बाद 15 फरवरी को देर रात करीब 400 की भीड़ ने एसपी कार्यालय को घेर लिया। उपद्रवियों ने कार्यालय पर पथराव किया और आगजनी भी की। प्रदर्शनकारियों के नियंत्रित करने के लिए रैपिट ऐक्शन फोर्स ने आंसू गैस के गोल दागे। गोली भी चली। इसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनें ही मृतक एसपी ऑफिस पर हमले में शामिल थे।

सोनिया गांधी के नामांकन पर आपत्ति

जयपुर। एडवोकेट योगेंद्र सिंह तंवर जो की राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया के इलेक्शन एजेंट भी हैं। उन्होंने सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन फार्म पर आपत्ति दर्ज करते हुए एक आपत्ति विधानसभा में प्रस्तुत की। इस आपत्ति में योगेंद्र सिंह के द्वारा सोनिया गांधी की इटली में जो प्रॉपर्टियों का हवाला दिया गया है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी की मांग की गई है। योगेंद्र सिंह ने बताया कि संविधान में यह प्रावधान है कि जब कोई भी एफिडेविट प्रस्तुत करता है तो उसको अपनी संपूर्ण संपदा की जानकारी जैसे कि वह संपदा कहां-कहां है, उसकी कीमत क्या है और वह कितनी है। यह सब देना अनिवार्य है। परंतु सोनिया गांधी के द्वारा जो फॉर्म राज्यसभा नामांकन के लिए भर गया, उसमें प्रस्तुत एफिडेविट में सिर्फ इटली में प्रॉपर्टी होने की बात कही गई है। जो कि संविधान के अनुसार उचित नहीं है। इस आपत्ति के दर्ज होने के बाद सोनिया गांधी से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब में इटली में दो-तीन शहरों में प्रॉपर्टी होने की बात कही, जिसको लेकर भी विपक्ष के वकील अभी संतुष्ट नहीं हैं।

एसटीएफ ने बरामद किए चार टाइम बम, एक आरोपी पकड़ा

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में शहर कोतवाली क्षेत्र से एसटीएफ की टीम के चार टाइम बम बरामद किए जाने की सूचना है। एक आरोपी भी पकड़ा गया है, हालांकि अभी पुलिस अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसटीएफ मेरठ की टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले से एक युवक को दबोच कर बृहस्पतिवार रात चार टाइम बम बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। मेरठ से बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया है। हालांकि, पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। बताया गया कि ये टाइम बम मुजफ्फरनगर में ही बनाए जा रहे थे। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके से एक आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है, उसके पास से चार टाइम बोतल बम (आईईडी) बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है, इन बम का इस्तेमाल किसी सुनियोजित षड्यंत्र में किया जाना था। जावेद ने पूछताछ में कबूल किया है कि यह बम खालापार इलाके में ही रहने वाली एक महिला ने ऑर्डर देकर बनवाए थे। टीम महिला की तलाश में जुटी है। एसटीएफ के एसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि इससे पहले भी यह टाइम बम बना चुका था।

आरबीआई ने पेटीम को दी राहत, 15 मार्च तक लेनदेन की सीमा

नई दिल्लीष भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए जमा और क्रेडिट लेनदेन की समयसीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों की दुविधा दूर करने के लिए स्वक्त (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके जवाब) जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस एफएक्यू के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से निकासी, रिफंड, सैलरी क्रेडिट, डीबीटी और बिजली बिल जमा करने से जुड़ी जानकारी दी है। आरबीआई की ओर से यह निर्णय बैंक द्वारा ग्राहकों और नियामक प्राधिकरणों के बारे चिंता जताने के बाद लिया गया है। आरबीआई ने कहा है, 15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समय-सीमा से विस्तारित) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, किसी भी ब्याज, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप इन या रिफंड आदि को कभी भी जमा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे।

सरकार विरोधी टूलकिटें सक्रिय हो चुकी हैं, कुछ आंदोलन खड़े हो गये, कुछ खड़े होने वाले हैं

डॉ. आशीष वशिष्ठ

लोकसभा चुनाव की घड़ियां जैस-जैसे समीप आ रही हैं, वैसे-वैसे देश का माहौल बिगाड़ने वाली टूल किट्स भी सक्रिय होनी शुरू हो गयी हैं। टूल किट्स की श्रृंखला में पहला प्रदर्शन देवभूमि उत्तराखण्ड के हलद्वानी में देखने को मिला। हलद्वानी में हिंसा की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है कि पंजाब से किसान आंदोलन के दूसरी टूल किट लांच हो चुकी है। आंदोलनकारी किसानों से सरकार लगतार बातचीत कर रही है, लेकिन किसानों की मांगों, उनके अड़ियल रूख और पर्दे की पीछे की राजनीति को देखकर मामला आसानी से निपटता दिखता नहीं है। इन दो टूलकिट्स के बीच पहलवान आंदोलन वाली तीसरी टूलकिट भी सक्रिय हो चुकी है। मामला पूरी तरह साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की छवि को हर मोर्चे पर डैमेज करना। अभी तो लोकसभा चुनाव तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। तिथियों की घोषणा होने तक कई दूसरी टूल किट्स भी सक्रिय हो जाएं तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है।

पिछले पांच साल में किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, संसद में शोर शराबा, शाहीन बाग, दिल्ली और नूह में दंगे, मणिपुर की हिंसा, चीन द्वारा जमीन कब्जाने की झूठी कहानियां फैलाना, पेगासस का शोर, फोन टैपिंग और हैंकिंग, अदाणी और अंबानी का विरोध ये सब किसी न किसी टूल किट का ही हिस्सा थे। समय, जरूरत और सामने वाले को देखकर मनचाही टूल किट को सक्रिय कर दिया जाता है और उस पर राजनीति की जाती है। मानवाधिकार की बातें की जाती हैं। छातियां पीटी जाती हैं, मगरमच्छी आंसू बहाए जाते हैं और देश में अशांति और अराजकता को माहौल दिखाकर अपने उल्लू सीधे किये जाते हैं। सरकार के समझौता करने पर उसे कमजोर और गलत साबित किया जाता है। और सरकार के अड़ने पर उसे तानाशाह और न जाने क्या-क्या क्रूर, असंवैधानिक और आमनवीय उपमाओं से नवाजा जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का विरोध करने कोई नयी प्रथा है। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष तो बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन जब विरोध केवल विरोध के लिए किया जाए तो उसमें सकारात्मकता का प्रतिशत न्यून हो जाता है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से विपक्ष सीधे तौर पर लड़ने की बजाय किसी न किसी टूलकिट के जरिए सरकार की छवि डैमेज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि सरकार की छवि डैमेज कर वो माहौल को अपने पक्ष में कर सकता है। वो अलग बात है कि उसे अपने प्रयासों में एक दशक में कामयाबी नहीं मिली। जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग और किसान आंदोलन के नाम पर साल भर से ज्यादा तक देश की राजधानी को बंधक बनाकर रखा गया, उससे साफ हो गया कि ये आंदोलन स्वत:स्फूर्त नहीं राजनीति से प्रेरित थे। सीएए और एनआरसी का विरोध, दिल्ली दंगे, नूह और हल्द्वानी की हिंसा। जगह भले ही अलग-अलग थीं लेकिन हिंसा करने का तरीका एक-सा था। सब कुछ पूर्व निश्चित और निर्धारित। अचानक कहीं से भीड़ आएगी, पथराव करेगी, आगजनी करेगी और भयंकर उपद्रव और उत्पात मचाकर एकदम गायब हो जाएगी।

वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। सरकार और किसानों के अपने अपने तर्क हैं। एमएसपी कानून बनाने की राह बहुत टेढ़ी और मुश्किलें भरी है, ये किसान भी जानते हैं। पर राजनीति से प्रेरित आंदोलनकारी कोई बात सुनने और मानने को तैयार नहीं। दो साल पहले किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ उसे पूरा देश जानता है। एक साल तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा तथाकथित किसानों ने। किसान आंदोलन पार्ट टू शुरू हो गया है। सरकार और आंदोलनरत किसानों की बीच बातचीत जारी है। इन सबके बीच भारतीय किसान यूनियन सिद्धुपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिममें वह कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था। उसे नीचे लाना है। डल्लेवाल के वीडियो से पूरे किसान आंदोलन पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि लोगों में चर्चा इस बात को लेकर थी ही कि आखिर अचानक ही इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। क्योंकि 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के 34 किसान संगठन विरोध कर रहे थे। जबकि यह आंदोलन मात्र 2 किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

डल्लेवाल के वीडियो सामने आने से संकेत मिल रहे है कि राम मंदिर बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जो छवि बनी थी, उसे गिराने के लिए राजनीतिक मंशा के तहत किसान आंदोलन को खड़ा कर लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया गया।

पुलिस और नक्सलियों के बीच दो घंटे मुठभेड़

कई नक्सली घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

जगदलपुर। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दो घंटे से अधिक समय तक चली इस मुठभेड़ में जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल, जवानों के द्वारा कुछ सामान भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है।

बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर डीआरजी, सीआरपीएफ की एक टीम गुरुवार की रात सर्चिंग पर निकले थे। जहां शुक्रवार की सुबह गमपुर में जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले हैं।

फिलहाल, मौके पर पुलिस फोर्स अभी भी मौजूद है। वहीं कुछ नक्सली सामान भी बरामद किए जाने की बात बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र गमपुर के जंगल में काफी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इस सूचना पर गुरुवार की रात जवान सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले। शुक्रवार की सुबह करीब नौ बजे के लगभग जवान जैसे ही नक्सलियों के इलाके में पहुंचे तो यहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।

जिसके बाद तुरंत ही जवानों ने भी बिना देर किए नक्सलियों के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने नक्सलियों की गोलीबारी का जमकर जवाब दिया। करीब 2 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की साजिश नाकाम

कांकेर। कांकेर पुलिस ने नक्सलियों के नाकाप मनसूबे पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने जंगल में आईईडी प्लांट कर रखा था। जवानों की सूझबूझ से आईईडी को बरामद कर वहीं नष्ट कर दिया गया है।

कांकेर पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि नक्सली अभियान के तहत कैंप से बीएसएफ 47 एवं डीआरजी के जवान एरिया डॉमिनेशन अभियान में ग्राम वटटेकाल के जंगलों की ओर रवाना हुए थे। उसी दौरान वटटेकाल के जंगलों में सुरक्षा बलों को हानि पहुंचाने की नियत से लगाया गया। आईईडी बरामद किया गया है।

आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। आस-पास के क्षेत्र में पुलिस बल, बीएसएफ और डीआरजी द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब हो कि एक दिन पहले ही नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से नक्सली अभियान निर्णायक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन कुछ लोग जगंल में और शहरों में रहकर ऐसे अपराधिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है कि जो अपराधिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। उनसे दूर रहे हैं और किसी तरह का सहयोग न करें। बल्कि अपराध को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करें।

75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा राज्य की संस्कृति की धरोहार

जगदलपुर। जगदलपुर विधायक किरण देव ने बजट सत्र के सदन में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछते कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने संस्कृति, धरोहर,परंपरा एवं मेला मंडई के उत्सव मनाए जाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। साथ ही हमारे बस्तर संभाग में विश्व विख्यात दशहरा, चित्रकूट महोत्सव ,रामाराम मेला, गोंचा पर्व एवं मेला,मंडई ,जात्रा एवं अपने परंपरा को समेटे हुए वर्ष भर बस्तर संभाग में कार्यक्रम होते रहते हैं, जो अपने आप में बस्तर की संस्कृति एवं कला को दर्शाता है।

इस अनोखी परंपरा को वर्तमान में भी बस्तर के आदिवासी जनमानस सभी परंपराओं को मनाते आ रहे हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इन सभी त्योहारों के लिए शासन के द्वारा कितनी अनुदान राशि वर्तमान में दिया जा रहा है

कहा, हमारा बस्तर दशहरा विश्व विख्यात है, जिसे देशभर से लोग बस्तर दशहरा देखने आते हैं। 75 दिनों तक चलने वाला हमारा बस्तर दशहरा अपने आप में हमारी संस्कृति को संजोए हुए है। हम सभी बस्तरवासी वर्तमान में भी धूमधाम और हर्षोउल्लास के साथ दशहरा बनाते हैं, साथ ही सुकमा में होने वाले रामाराम मेला ,चित्रकूट महोत्सव, गोंचा पर्व एवं गांव भर में होने वाले मेला ,मंडई एवं देवगुडी में होने वाले पूजा पाठ के लिए हमारे बस्तर की पहचान है।

इन सभी परंपराओं का संजोग कर रखना हमारा दायित्व है। सवाल करते हुए उन्होंने संस्कृति एवं

पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इन सभी त्योहारों के लिए शासन के द्वारा कितनी अनुदान राशि वर्तमान में दिया जा रहा है, वहीं अनुदान राशि को बढ़ाने की बात भी सदन में रखी, जिस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि बस्तर दशहरा के लिए पूर्व में पर्यटन एवं धर्मस्थ विभाग से 35 लाख दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब विश्व प्रसिद्ध दशहरा के लिए 50 लाख रुपये हर वर्ष अनुदान राशि दी जाएगी।

रामाराम मेले के लिए पूर्व में 10 लाख रुपए दिया जाता था,जिसे बढ़ाकर15 लाख रुपये, चित्रकूट महोत्सव के लिए पूर्व में 10 लाख रुपये दिए जा रहे थे, उसे बढ़ाकर 15 लाख और गोंचा महापर्व के लिए पूर्व में 3 लाख रूपये दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

जनसमस्या निवारण शिविर ने बढ़ाई लोगों की टेंशन, स्टेशन रोड हुआ जाम

सक्ती। शहर में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सक्ती के रेलवे स्टेशन रोड में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर में यह शिविर लगाया गया है। जिसमें सभी विभागों के शिविर लगाए गए हैं। यहां लोगों की समस्या सुनी जा रही है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह शिविर लोगों की समस्या दूर करने की बजाए लोगों के लिए समस्या बन गया है।

दरअसल, शिविर का आयोजन शहर के अंदर किया जा रहा है। जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जिसके चलते सक्ती के कई मार्ग पूरी तरह से जाम हो गए हैं। सक्ती का रेलवे स्टेशन रोड पूरी तरह जाम हो गया है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। हजारों लोगों की भीड़ एक साथ इस रोड से होकर शिविर पहुंच रही हैं। जिसके चलते सड़क पूरी तरह जाम हो गई है। कई लोग जिन्हें ट्रेन पकड़नी थी वो भी समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए और उनकी ट्रेन छूट गई।

जिलेभर से अपनी समस्या लेकर आए कई लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। क्योंकि कई विभागों के अधिकारी मौके पर नहीं मिले। उनकी समस्या सुनने वाला मौके पर कोई नहीं था।

ज्यादातर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन दोपहर तक इसका काम चालू नहीं हो सका और कई लोग निराश होकर वापस लौट गए।

नगर के लोगों का कहना है कि जिला स्तरीय आयोजन है। जिसमें जिले भर से हजारों लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं। इतना वृहद कार्यक्रम नगर के अंदर करना अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई लोग जिन्हें ट्रेन पकड़नी थी उनकी ट्रेन छूट गई। वहीं कई लोग जो अस्पताल जा रहे थे उन्हे भी घंटो जाम से होकर गुजरना पड़ा।

बस्तर में गैंगवार : एक गैंग के गुर्गों ने दूसरे गैंग के सरगना पर चलाई गोली

जगदलपुर। जगदलपुर शहर के नए बस स्टैंड पर पैसों को लेकर दो गैंग में विवाद हो गया। एक गैंग ने पिस्टल निकाल कर गोली चला दी। इस घटना में कोई घायल तो नही हुआ, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही एक टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पैदल ही न्यायालय तक ले जाया गया, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

बस्तर पुलिस ने बताया कि नया बस स्टैंड पर 14 फरवरी की रात में शहर के एक गैंग के गुर्गों द्वारा दूसरे गैंग के सरगना को पिस्टल से मारने की धमकी देते हुए फायर कर जान से मारने का असफल प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नया बस स्टैंड सुलभ शौचालय के पास में प्रार्थी अमित शर्मा को नाथू व टाकलू भैय्या का पैसा वापस नहीं लेने की बात कहते हुए राज दुग्गा द्वारा अपने पास एक पिस्टल जैसे दिखने वाले हथियार निकालकर लहराते हुए गोली चला दी। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना बोधघाट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई। टीम के प्रयास से चार आरोपी राज दुग्गा, चिराग साहू, किशोर चालान और मोहम्मद अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। ये सभी घटना के बाद ओडिशा चले गए थे। आरोपियों की जवाबदेही पर आरोपी त्रिनाथ दुर्गा और हेमंत ध्रुव को जगदलपुर से पकड़ा गया।

बताया जा रहा है कि दोनों गैंग के गुंडों के बीच पुरानी रंजिश है। बीते दिनों हुए मारपीट की घटना को लेकर दो गैंग आपस में भिड़कर बहस करने लगे। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। एक गैंग ने अपना पिस्टल निकाल लिया। हालांकि फायर नहीं होने के कारण बड़ी घटना होने से टल गई। घटना के बाद यह मामला बोधघाट थाने पहुंचा।

नक्सलवाद के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी : एसपी

नक्सली मददगारों पर होगी कड़ी कार्यवाही

कांकेर। जिले में नवपदस्थ एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने प्रेस से चर्चा करते कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नक्सलवाद के विरूद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। कांकेर जिले का काफी भाग नक्सल प्रभावित है। यहां नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाएगा।

नक्सलियों के अलावा उनके मददगारों चाहे वे किसी भी रूप में मदद करते हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों को सामान तथा अन्य चीजें सप्लाई करने वाले, उनके लिए शहरों में काम करने वाले, उनके षडयंत्रों में शामिल हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग सावधान हो जाएं तथा नक्सलियों के लिए काम करना बंद कर दें। खासकर नौजवान साथी नक्सलियों से दूर रहें। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का पता लगाया जाएगा तथा फिर चाहे वो जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आम जनता के लगातार संपर्क में रहेगी तथा उनके हितों के लिए काम करेगी। उन्होने कहा कि सट्टा तथा जुआ कहीं नहीं चलना चाहिए। इस पर कड़ाई से कार्रवाई जिले में कराई जाएगी। पुलिस में सेटिंग का कोई भी सिस्टम नहीं होगा। पहले से कहीं चल रहा होगा तो उसे भी बंद कराया जाएगा। इस तरह के मामलों में कहीं भी पुलिस की संलिप्ता पाई गई तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

जिला अस्पताल में ब्लड बैंक स्टोरेज की सुविधा शुरू

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसी क्रम में आपातकालीन सुविधाओं में जिला अस्पताल में ब्लड बैंक स्टोरेज सुविधा शुरू हो गई है। पिछले कई वर्षों से ब्लड बैंक की मांग आम नागरिकों के द्वारा की जा रही थी। ब्लड बैंक स्टोरेज सुविधा शुरू होने पर बड़ी संख्या में आम लोगों और जनप्रतिनिधियों ने ब्लड डोनेट किया। बता दें कि ब्लड बैंक की स्थापना के साथ ही मरीजों को उनकी जरूरत के हिसाब से किसी भी ग्रुप का ब्लड की उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी और मरीजों को तत्काल ब्लड मिल जाएगा। मरीजों को अब ब्लड के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। अब गंभीर मरीजों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार, पिछले सप्ताह जिले दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक का विधिवत उद्घाटन भी किया था।

एसईसीएल खदान में कबाड़ चोर गिरोह सक्रिय

कोरबा। कोरबा जिले में कबाड़ चोरों के खिलाफ एसपी के निर्देश में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। अभी पिछले दिनों ही एसईसीएल के टीलाईन स्टोर से भारी मात्रा में कबाड़ की चोरी कर ली गई थी, जिसके चार आरोपी पकड़े गए थे। मामले में एक और कबाड़ व्यवसाई तनवीर अहमद की संलिप्तता मिली थी और उसे भी गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बार बार होने वाली चारियों तो लेकर पुलिस प्रशासन भी हैरान है। उनका कहना है कि स्टोर से बार-बार भारी मात्रा में कबाड़ चोरी हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर प्रबंधन के पास कोई जानकारी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी पुलिस ने तनवीर अहमद के रामनगर बायपास मार्ग पर स्थित यार्ड पर छापा मारा, जहां दस टन कबाड़ को जप्त किया था। इसकी कीमत करीब दो लाख रुपए आंकी गई। मामले में तनवीर अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मानिकपुर चौकी प्रभारी प्रेम साहू ने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले एसईसीएल मानिकपुर खदान से लगभग 30 लाख कीमती लोहे का टी राड कबाड़ स्टोर से गायब हो चुकी है।

पुलिस को बड़ी कामयाबी, दो करोड़ का गांजा जब्त

कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से दो करोड़ रुपये की कीमत के 10.50 क्विंटल गांजा को जब्त किया है। यह कार्रवाई कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना ने की है। एसपी डाक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में चावल की सप्लाई के आड़ में गांजे का अवैध परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने थाना के पास नाकेबंदी कर वाहन को रूकवाया। वाहन में अलग-अलग पॉलीथिन में करीब 10 क्विंटल 50 किलो गांजा था। गांजे को उड़ीसा से आगरा ले जाया जा रहा था। आगरा से इसे देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। कबीरधाम जिले में यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन मालिक और इस अवैध कारोबार में जुड़े लोगों के बारे में खोजबीन की जा रही है।

महिला मरीज की हत्या का प्रयास, अस्पताल में चीखपुकार

कोरबा। अजब-गजब घटनाओं को लेकर कोरबा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। बीती रात को अस्पताल के महिला वार्ड में एक नशेड़ी ने प्रवेश कर जमकर उत्पात मचाया। उसने एक मरीज का गला दबाने का प्रयास किया। चिल्लाने पर आरोपी शराबी भाग निकला। रात 12 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला वार्ड में अजीब स्थिति बन गई। जब एक नशेड़ी ने यहां पहुंचकर खूब तमाशा किया। पुरानी बस्ती निवासी रानू महंत पांच दिन से महिला वार्ड में भर्ती है। जिससे नशेड़ी ने अभद्रता की और उसका गला दबाने का प्रयास किया। उसके चिल्लाने पर नशेड़ी भाग खड़ा हुआ। मरीज रानू महंत ने बताया कि आरोपी युवक की माँ भर्ती है। जिसके साथ युवक देख रेख करने रुकता है। देर रात 12 बजे आया और हल्ला किया। गाली-गलौज करते हुए गला दबाने लगा और वो बेड से नीचे गिर पड़ी। जिसके बाद वार्ड में शोर मच गया और युवक भाग खड़ा हुआ। आरोपी के खिलाफ शिकायत जिला अस्पताल चौकी पुलिस से की है।

हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में लगी आग

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में आग लग गई। घर में सोए पति और पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पुलिस पहुंची। जिसके बाद तत्काल अग्निशमन दल को सूचना दी। घर में घुसे तो देखा दोनों पति और पत्नी बेहोश हालत में पड़े थे। दोनों को पुलिस अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि आज अलसुबह करीब चार से पांच बजे की घटना है। हाउसिंग बोर्ड निवासी वर्गीस चेरियन (65 वर्ष) और पत्नी जॉली चेरियन (60 वर्ष) दोनों घर में अलग-अलग कमरे में सोए थे। सामने वाले कमरे में कोई नहीं था। जहां का बेड पर रखें गद्दे में आग लग गई। गद्दे का धुंआ पूरे घर में फैल गया। घर के कमरों की खिड़कियां बंद थी। वेल्टिलेशन नहीं होने के कारण दोनों का दम घुट गया। अलग-अलग कमरे में सोए पति और पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश और दोनों घायलों को बाहर निकाल दिया।

एमएसपी गारंटी के लिए पीएम के नाम किसानों ने सौंपा ज्ञापन

गरियाबंद। संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एवं अंशकालिक स्कूल कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक राजिम में प्रदर्शन कर तहसीलदार राजिम रूपेश मरकाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में किसानों ने कहा कि बीते दो साल पूर्व कृषि सुधार के नाम पर लाये गए कृषि, किसान और आम उपभोक्ता विरोधी कॉरपोरेट हितैषी कानूनों के खिलाफ देश के किसान दिल्ली सीमाओं पर 13 महीने तक आंदोलनरत रहे तथा केंद्र सरकार की लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन से वापस हुए थे, जिसमें 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी किसानों की मांगों के ऊपर केन्द्र सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं किया।

कॉरपोरेट कंपनियों के हित में श्रम कानूनों में बड़ी बदलाव कर चार श्रम सहिंता बनाया जो घोर मजदूर विरोधी है, जिससे मजदूर सुरक्षित व स्थायी रोजगार से वंचित हो रहे हैं इसे रद्द करने की मांग देश के मजदूर संगठनों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में अंशकालिक एवं अनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी विभागीय कार्यालयों में नियमित कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है।

किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए डॉ एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन घोषित करने व खरीद की कानूनी गारंटी देने से स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का सम्मान और भी बढ़ जाता। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा मोदी गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा और बड़ी राज्यों में जीतकर आये। इसका तात्पर्य है कि राज्यों के शासन को भी मोदी गारंटी के आधार पर ही संचालित किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए इसे राज्यों तक सीमित न रखकर देश की जनता को गारंटी देनी चाहिए।

संयुक्त किसान मोर्चा एवं संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के देशव्यापी ग्रामीण भारत बंद के आह्वान पर आज 16 फरवरी 2024 को पं. सुन्दरलाल शर्मा चौक राजिम में हम अपना विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संयुक्त किसान मोर्चा व संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की मांगों के साथ साथ निम्नलिखित मांगो को पूरा करने का अनुरोध किया है।

1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो। 2. मजदूरों को कॉरपोरेट कंपनियों की गुलाम बनाने वाली चार श्रम सहिंता वापस लो। 3. कोयला उत्खनन के लिए हसदेव अरण्य का विनाश करना बंद करो। 4. जल, जंगल, जमीन से आदिवासियों की बेदखली पर रोक लगाओ। 5. माओवाद के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की प्रताड़ना बंद हो। 6. छत्तीसगढ़ में गेल इंडिया पाईप लाईन के प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। 7. अंशकालिक एवं अनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।

बलरामपुर में बारिश और बर्फबारी सड़कों पर छाया घना कोहरा

बलरामपुर। चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए बलरामपुर में मौसम ने करवट बदली है। पिछले चार दिनों से जिले में हल्की बारिश हो रही है। कुछ क्षेत्रों में तो ओलावृष्टि भी हुई है। शुक्रवार की सुबह से बलरामपुर की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। जिले में बारिश की वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है।

बलरामपुर में आज शुक्रवार की सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे हुए बलरामपुर में फरवरी और मार्च तक ठंड का प्रभाव रहता है।

बलरामपुर में बीते रविवार से मौसम में बदलाव हुआ जिसके बाद बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं साथ ही अलाव जलाकर ताप रहे हैं।

बलरामपुर में बारिश और बर्फबारी की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को दोपहर के समय अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि रात के समय न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों बाद जिले में मौसम साफ हो सकता है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंप पुलिस का ही नहीं विकास का भी होगा कैंप : मुख्यमंत्री

नये 14 कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में लागू होगी नियद नेल्लानार योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू पीएम जनमन योजना की तरह दिये जाएंगे लाभ

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांवों के लिए नियद नेल्लानार योजना अर्थात आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ करने की बड़ी घोषणा की। इस योजना के तहत नक्सल आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये कैंपों के 05 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। नए कैंप पुलिस का ही नहीं विकास का भी कैंप होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के लिए 20 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है, यदि भविष्य में केंद्र एवं राज्य से और बजट की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार वह भी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध होगी। योजनाओं के सतत लाभ के मूल्यांकन और मानिटरिंग के लिए डैश बोर्ड तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से इसकी सतत समीक्षा की जाएगी और सुनिश्चित किया जावेगा कि कोई भी परिवार इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रह पाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नियद नेल्लानार योजना के संबंध में कहा कि इन गांवों के तेजी से आर्थिक विकास के लिए यह योजना तैयार की गई है। इन गांवों के निकट 14 नये कैंप खोले गये हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था हो और ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं के सेचुरेशन के साथ लाभ दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों के निकट 14 नये कैंप खोले गये हैं। वहां 05 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गांवों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास हेतु कार्रवाई की जाएगी। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा ब्लाक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए इन ग्रामों में जनसुविधा शिविर में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा स्थल पर ही इसका निराकरण किया जाएगा।

पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री की इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इस योजना से बस्तर के आदिवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़क और गांव का विकास नहीं हुआ है, इस योजना में उस ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

सुशासन और राम राज्य लाने का काम जारी : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज वनबंधु परिषद रायपुर चेप्टर और महिला के एकल अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम राजधानी के महेश्वरी भवन में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में वनबंधु पहुंचे हैं। कार्यक्रम में वार्षिकोउत्सव, दानदाता और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सकरार ने 5 साल में प्रदेश में जो भ्रष्टाचार किया उसे रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि एकल अभियान के लोगों ने शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले एकल अभियान की ओर से मतदाता जागरण का काम पूरे प्रदेश में किया गया है। एक-एक घर में लोगों से मिलकर बताया की किस तरह से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आप लोगों ने मतदाता जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया है। भाजपा को 54 सीट मिला है। 46 प्रतिशत से ज्यादा सीट प्रतिशत रहा है। इसमें एकल परिवार का भी बड़ा सहयोग है।

भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम जो हमारे भाचा राम के हैं, 500 सालों के संघर्ष के बाद सौभाग्य से हमको मिला है। हम माता कौशल्या की धरती वाले हैं। जब भगवान राम प्रतिक्षित हुए तो हमने खुशियां मनाई। सबके सहयोग से यहां से 11 ट्रक सुगंधित चावल भेजा गया है। यहां से 100 से ज्यादा डॉक्टर गए हैं। हमारे 5 संस्थान चलाने वाले राशन भी भेजे गए हैं और भगवान राम के भक्तों को भोजन करवा रहे हैं। अलग-अलग तरीके से खुशियां मना रहे हैं। सबको हरी झड़ी दिखाकर हमको अवसर मिला है। पहली ट्रेन दुर्ग से गई और दूसरी ट्रेन रायपुर से गई है। एक गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सीएम का दायित्व मिला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उन्होंने वादा किया था यह सरकार बनने के बाद राम राज आएगा। आज मोदी की गारंटी जो पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारी सरकार उनकी गारेंटी पूरी करने लग गई है।

सीएम साय ने कहा कि आचार संहिता लगने के पहले किसानों के खाते में एकमुश्त राशि भेज देंगे। मार्च महीने से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 12 हजार रुपये की दर से हर महीना एक हजार रुपये पैसा जाना शुरू हो जाएगा। बीमा योजना शुरू होगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 5 साल में प्रदेश में भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा, आज कितने लोग जेल के अंदर हैं, उनको बेल भी नहीं मिल रही है। एक सुशासन और राम राज्य लाने का काम हम कर रहे हैं। अच्छा गांव योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव ने कहा, आपका अच्छा गांव योजना कल हमने विधानसभा में शुरू की है। बस्तर के 5 जिलों के लिए यह योजना शुरू की गई है। 14 पुलिस कैंप खुले हैं। जितने भी गांव उस कैंप के अंदर आएगी वहां लोगों को सुविधा मिलेगी। 14 हजार घरों में बिजली नहीं पहुंचा है, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष मिंज ने आयोग का प्रतिवेदन सौंपा

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सरजियस मिंज ने आयोग के कार्यों की जानकारी दी और आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025-2030 की अवधि के लिए राज्य के नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर उसे सुदृढ़ करने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्य काल ढाई वर्ष का था। आयोग ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात अपनी अनुशंसाएं सौंपी हैं। प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं विभागों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव जे.एस. विरदी, सुश्री पायल गुप्ता और श्री एम.एन. राजुरकर उपस्थित थे।

बस्तर विवि का दीक्षांत समारोह 5 मार्च को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे शामिल

जगदलपुर। बस्तर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 5 मार्च को आयोजित होगा, दीक्षांत समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और बस्तर के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में मुख्य वक्ता के तौर प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी शामिल होंगे। कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 5 मार्च को दीक्षांत आयोजित किया जा रहा है, इसमें 93 छात्रों को मेडल दिए जायेंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि दीक्षांत में ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होकर छात्रों को अपना उद्बोधन दें। विदित हो कि बस्तर विश्वविद्यालय में दो वर्ष के बाद दीक्षांत आयोजित हो रहा है, इस वर्ष इसे भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है।

अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा, व्यापमं ने बनाई नई वेबसाइट

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नई वेबसाइट बनाई है। सर्वर डाउन से होने वाली समस्या से बचने के लिए इस वेबसैट को बनाया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन फार्म भरते समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय और परीक्षा परिणाम जारी उपरांत अत्यधिक संख्या में हिट्स होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती थी। इस समस्यों से बचने के लिए नई वेबसाइट शुरू की गई। यह वर्तमान में व्यापमं की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति चलेगी। पहले की वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने नई वेबसाइट भी शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में संचालित वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फार्म भरते समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ज्यादा हिट्स होने से अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापमं की ओर से एक नई वेबसाइट https://vyapamaar.cgstate.gov.in बनाई गई है। इस वेबसाइट में सिर्फ मुख्य सूचनायें, नवीन पंजीयन, अभ्यर्थी लॉगिन और परीक्षा परिणामों को प्रदर्शित किया जायेगा। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित व्यापमं की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पहले की तरह चलती रहेगी।

भूपेश बघेल ने नक्सल नीति पर सदन में सरकार से किया सवाल

■ **दो महीने में क्या प्रगति हुई?**

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल नीति पर सरकार को सदन में घेरा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को लेकर सरकार अलग-अलग बयान आता है। कभी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करने की तो कभी कार्रवाई करने की बात कही जाती है। स्थिति स्पष्ट नहीं है। सरकार को आए 2 महीने हो गए, क्या प्रगति हुई? इसके बारे में सरकार मौन है। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन नक्सल नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं की। बस्तर में जबरदस्त दहशत का माहौल था, नक्सली गतिविधि पर कोई कंट्रोल नहीं था। 5 सालों में हमारी सरकार ने नीति बनाई, उसके साथ-साथ पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया। जनता और पुलिस के बीच व्यवहार में परिवर्तन करवाया कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। पहले ये सड़कों का विरोध करते थे। सड़क को पहले मिलिट्री फोर्स आवागमन के लिए सुविधा मानते थे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने तेंदूपत्ता के रेट में वृद्धि की, मिलेट के रेट पर वृद्धि की, कर्ज माफ की, 2500 में धान खरीदी की, जमीन वापस की, वहां लोगों के जेब में पैसा पहुंचा, उससे परिवर्तन आया। सुविधाएं बढ़ाई, शिक्षा सुविधा विस्तार किया, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा। सैकड़ों आदिवासी जेल में सालों से बंद थे। बस्तर में विश्वास का वातावरण हमने निर्मित किया, यही कारण है कि 5 सालों में 600 सबसे ज्यादा गांव नक्सली मुक्त हुए। भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि कैंप के 5 किमी दायरे में विकास करेंगे। इसकी शुरुआत हमने पहले ही कर दिया था। इसी कारण से स्थिति बनी। किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी के पास जॉब कार्ड नहीं था, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। सारे कैंप लगाकर हमने किया। इसके कारण से परिवर्तन आया, वरना सिलगेर कोई जा नहीं पता था, अब तो बसें चलने लगी। 5 सालों में कभी कैंपों में हमला नहीं होता था, लेकिन 2 महीने की सरकार में कितने बार कैंप में हमले होने लगे। पहले भी ऐसा हुआ था, और अब भी ऐसा ही हो रहा है।

भिलाई में महादेव सट्टा एप का पैनल ऑपरेटर गिरफ्तार

■ **काली कमाई से दुबई में खरीदी थी प्रॉपर्टी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय के टीम की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम एक-एक करके महादेव सट्टा एप से जुड़े हुए लोगों को पकड़ रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने भिलाई से 25 साल के नीतीश दीवान को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट में आरोपी को पेश किया। जहां कोर्ट ने आरोपी को 8 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है।

रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तार नीतीश दीवान को 24 फरवरी तक 8 दिनों के लिए रिमांड पर ईडी को सौंपा है। नीतीश दीवान भिलाई के वैशाली नगर का रहने वाला है, जो महादेव सट्टा एप में पैनल ऑपरेटर का काम करता था।

ईडी वकील सौरभ कुमार पांडेय ने कहा शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नीतीश दीवान को कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 8 दिनों की रिमांड मंजूर की है। ईडी आठ दिनों तक नीतीश दीवान से पूछताछ करने के बाद दोबारा 24 फरवरी को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी।

जानकारी के मुताबिक, नीतीश दीवान दुबई में 2 सालों तक महादेव सट्टा एप के पैनल ऑपरेटर टीम में था। नीतीश ने महादेव एप के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। नीतीश का काम पैनल ऑपरेटर को समय-समय पर चेक करना होता था। महादेव सट्टा एप के माध्यम से आने वाली काली कमाई को प्रमोटर के कहने पर अपने अकाउंट के जरिए नीतीश इधर-उधर करता था। सट्टे के पैसों को नीतीश दीवान के जरिए इन्वेस्ट किया गया था। नीतीश के नाम से दुबई में कई प्रॉपर्टी भी खरीदी गई है।

दरअसल, महादेव सट्टा एप और मनी लांड्रिंग के मामले में कोलकाता से गिरफ्तार आरोपी नितिन टिबरेवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नितिन टिंबरेवाल और अमित अग्रवाल की न्यायिक रिमांड को लेकर भी सुनवाई हुई।

भारत बंद : कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा-

लगातार किसानों की मांगों को टालती रही सरकार

■ **पहले 700 से अधिक किसानों की देने पड़ी थी आहुति**

रायपुर। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उधोराम साहू और रायपुर नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दूबे ने संयुक्त प्रेस कांग्रेस ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने किसानों के भारत बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की लेकिन आज दो साल में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई।

उधोराम साहू ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी साढ़े सात सौ किसानों को आहुति देनी पड़ी थी। केंद्र सरकार लगातार उनकी मांगों को टालती रही। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस इसका समर्थन करती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबिकापुर में केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दी है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा हमारा किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा समर्थन है। सात सौ से अधिक किसानों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से बात की। एक कमेटी गठित की लेकिन आज दो साल बीत गए इसकी एक बैठक तक नहीं हुई। सरकार देश में अलग-अलग फसल लेते हैं। मौसम आधारित खेती है, इसके बाद भी किसानों को कोई समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है।

कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रमोद दूबे ने कहा, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हमेशा एमएसपी की बात करते थे। आज बीजेपी के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से एमएसपी को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी का मतलब ये नहीं की सरकार किसानों की सारी उपज खरीदेगी बल्कि इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदेगी। केंद्र किसानों को तुच्छ समझती है,बड़े नेता अफवाह फैलाते हैं।

अब डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट होगा खत्म : स्वास्थ्य मंत्री

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शुक्रवार को विधानसभा सदन में बड़ी घोषणा की। श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि, ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है। इससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

विधानसभा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि, यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है, जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है। अटैचमेंट करना जरूरी हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अकारण ही अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है, जिसे खत्म करना आवश्यक है।

यानी कि अब स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों का अटैचमैंट खत्म कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि जल्द ही इसे लेकर आदेश भी जारी किए जाएंगे। बता दें कि जब से मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने पदभार संभाला है, वो एक्टिव है। लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। वहीं, अस्पताल में मरीजों का हालचाल भी जान रहे हैं, जिस किसी अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है, उसे लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री सख्त हैं।

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
MAHANADI CIRCLE, RAIPUR (CHHATTISGARH)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(Second Call)

System Tender No. 152798/ NIT No.: 36/SAC/23-24 Dated: 13.022024

Online Tenders are invited for the following works up to 01.03.2024 at 17.30 Hours

Name of work - Decorative Illumination work in Rajim Suspension Arch Bridge for Ram Vangaman Path at Block Rajim, District - Gariyaband.

Probable Amount of Contract: **Rs. 136.52 Lakhs (As per S.O.R dated 01.08.2010 and amended upto dated 01.08.2014 and Market Rate).**

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal **(https://eproc.cgstate.gov.in) from Date 20.02.2024, at 17.31 Hours. (IST) onwards.**

NOTE:- All eligible/intrested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-procurement portal **(https://eproc.cgstate.gov.in)** and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to download the tender documents andparticipate in the subsequent bidding process.

Executive Engineer
Water Management Division No. 1, Raipur
For, Superintending Engineer
Mahanadi Circle, Raipur (C.G.)
जी-07834/5

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मंडल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना
(प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई.टी. क्र./सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)
1	2	3
224/152720	S.R./M.O.W. WORK OF RESIDENTIONAL & NON RESIDENTIONAL BUILDING WORK UNDER RAJBHAWAN SECTION P.W.D. NIRMAN SUB. DIVISION -2 RAIPUR (C.G.)	रू. 50.00 लाख
225/152721	WHITE WASHING COLOUR WASHING DISTEMPERING , PAINTING,EXTERIOR & INTERIOR PAINT WORK AT RAJBHAWAN & RAJBHAWAN STAFF QTR. RAIPUR.	रू. 49.99 लाख
226/152722	SPECIAL REPAIR, MOW & OTHER DEPOSITE WORK'S IN BLOCK-A TO BLOCK-G DR. B.R. AMBEDKER MEMORIAL HOSPITAL BUILDING'S UNDER CONSTRUCTION SUB DIVISION NO.-02 AT - RAIPUR (C.G.)	रू. 40.00 लाख
227/152723	S/R , M.O.W. & DEPOSIT WORK UNDER STATE HEALTH CENTER , JAIL HEAD QUATER , VETERINARY HOSPITAL , PWD CONSTRUCTION SUB DIVISION NO.2 RAIPUR (C.G.)	रू. 25.00 लाख

डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 29.02.2024 समय सायं 5:30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., रायपुर मंडल क्र.-1 (छ.ग.)
जी-07805/6

चुनावी बिसात पर विपक्षी गठबंधन का बिखराव

राजकुमार

अगर नैतिकता के प्रति आग्रही न बनें, तो अपनी सरकार को चुनौती के इरादे के साथ बने 28 विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के अंतर्विरोधों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जैसी बिसात बिछायी है, वह राजनीतिक प्रबंधन की मिसाल है। अपनी सरकार की 'हैट्रिक' में उन्हें जिन-जिन राज्यों में, जिन-जिन क्षत्रपों से मुश्किलें पेश आ सकती थीं, वहां ऐसी पेशबंदी की है कि चुनाव से पहले ही पासा पलटता दिख रहा है। बदलते परिदृश्य में, सात महीने पहले जोर-शोर के साथ बना 'इंडिया' बिखराव के कगार पर है। सूत्रधार कहे गये नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौट गये हैं, तो जयंत चौधरी के भी पाला बदल में औपचारिक घोषणा ही शेष है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो आप ने भी पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। अस्सी सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाला बिहार, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र और 28 सीटों वाला कर्नाटक भाजपा के प्रमुख शक्ति स्रोतों में रहे हैं। 'इंडिया' बनने के बाद चुनावी गणित गड़बड़ाता भी दिख रहा था। पर पिछले वर्ष के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांगेस को जबरदस्त मात दे कर केंद्र में सरकार की 'हैट्रिक' का नारा देने के बाद से ही भाजपाई रणनीतिकार चुनावी बिसात बिछाने में जुटे हैं। चुनावी चुनौती पेश कर सकने वाले 'इंडिया' को तार-तार करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा ने संयोजक न बनाये जाने पर नीतीश की निराशा को भांपा, लालू परिवार से उनके संशय को हवा दी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और एक-दूसरे के लिए बंद बताये जानेवाले खिड़की-दरवाजे सब खुल गये। बिहार का चुनावी समीकरण फिर भाजपा के पक्ष में झुक गया है। अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली मायावती के मन में जो भी हो, उससे अंततः लाभ भाजपा को ही होगा। फिर भी सपा-कांग्रेस-रालोद मिलकर चुनौती दे सकते थे। इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भी 'इंडिया' के अंतर्विरोधों का लाभ उठाया। रालोद को दी सात सीटों में से भी तीन पर सपा और एक पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने का दबाव अखिलेश ने जयंत पर बनाया, जिसके बीच भाजपा ने अपनी बिसात की जगह बना ली। लगभग अखिलेश जितनी ही लोकसभा सीटें तथा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में हिस्सेदारी के वादे के अतिरिक्त, दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से भी नवाज दिया। अब कांग्रेस-सपा के लिए भाजपा को चुनौती दे पाना संभव नहीं होगा। बेशक 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में भाजपा का दांव फिलहाल उलटा पड़ गया, पर 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद कांग्रेस में जारी सेंधमारी भी उसी चुनावी बिसात का हिस्सा है। पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा से शुरू यह सेंधमारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर ही नहीं रुकेगी। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद अचानक बड़े भाई वाली मुद्रा में आ गयी कांग्रेस अगर नहीं संभली, तो महाराष्ट्र में भी भाजपा को चुनावी समीकरण ठीक करने में अधिक मुश्किल नहीं आयेगी। पिछले वर्ष कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद वहां भी भाजपा ने नये सिरे से चुनावी बिसात बिछायी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर से गठबंधन के अतिरिक्त, बीएस येदियुरप्पा के बेटे बिजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की घर वापसी हो गयी है। क्रमशः 13 और सात लोकसभा सीटों वाले पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के पीछे भाजपा की भूमिका देखना शायद जल्दबाजी हो, पर कांग्रेस को लगने वाला हर झटका उसके लिए राहतकारी तो होता ही है। दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य- आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु- अभी तक भाजपा की पहुंच से बाहर रहे हैं। इन राज्यों में चुनावी बिसात भाजपा के लिए आसान नहीं। पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा से उसने कोशिश अवश्य की है।

एग्जिट रूट तलाश रहा गांधी परिवार

अभिनय आकाश

अरे ओ आसमाँ वाले बता इस में बुरा क्या है
खुशी के चार झोंके गर इधर से भी गुज़र जाएँ

साहिर लुधियानवी का ये शेर देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के वर्तमान हालात पर एकदम मौजूं हैं। गांधी-नेहरू परिवार की राजनीतिक सरजमीं जिस उत्तर प्रदेश से रही वहां कांग्रेस का जनाधार एकदम खत्म होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, रायबरेली, अमेठी हो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने उत्तर प्रदेश की किसी ने किसी सीट को अपना गढ़ बनाया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवारलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ते थे। फूलपुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली को अपना गढ़ बनाया। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने भी रायबरेली से चुनाव जीता था। जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर से चुनाव जीता था। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी फूलपुर सहित चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी ने अमेठी लड़ा। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ा। राजीव और सोनिया के बेटे राहुल गांधी भी अमेठी से ही चुनाव लड़ते रहे। उमा नेहरू के नाती अरुण नेहरू रायबरेली से चुनाव लड़े। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से और उनके बेटे वरुण सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते रहे।

इन सभी में से रायबरेली ऐसी सीट रही है जहां कांग्रेस आजादी के बाद से वह 17 आम चुनाव में से केवल तीन बार हारी है। इसी तरह वर्ष 1967 में बनी अमेठी सीट पर भी कांग्रेस केवल 3 बार हारी है। नेहरू गांधी परिवार की जगह भले ही कश्मीर से जुड़ी बताई जाती हो लेकिन नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत उत्तर प्रदेश होती है। जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों ही ब्रिटिश हुकुमत में इलाहाबाद हाईकोर्ट वकील थे। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था। मोतीलाल और जवाहरलाल दोनों ही इलाहाबाद में रहते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। यानी इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोनों ही नेताओं की राजनीतिक कर्म भूमि रही है।

वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का अपना पहला चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से ही जीता था। वही जवाहरलाल नेहरू 1962 में अपना आखिरी चुनाव पर फूलपुर में ही लड़ा था। और सुनाओ मैं नेहरू ने राम मनोहर लोहिया को 50000 से ज्यादा वोटो से हराया था। 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने फूलपुर से ही चुनाव लड़ा भी और जीत भी। साल 1962 में जवाहर लाल नेहरू के चचेरे भाई श्याम लाल नेहरू की पत्नी उमा नेहरू राज्यसभा पहुंची थी ये पहली बार था जब गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा गया हो। इसके बाद 1964 में इंदिरा गांधी वो दूसरी सदस्य थी तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा गई थीं। लेकिन 1967 में इंदिरा ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब 57 साल बाद गांधी परिवार से कोई सदस्य राज्यसभा से जाने वाला है।

अमेठी सीट 1967 में बनी थी और तभी से नेहरू गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य इस सीट से चुनाव जीतता रहा है। 1977 में इंदिरा ने रायबरेली और उनके बेटे संजय ने अमेठी से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में दोनों की ही करारी हार हुई थी। 1999 में अमेठी और बिलारी और फिर 2004 से लेकर 2019 तक रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी अबकी बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। ऐसे में दवा यह भी किया जा रहा है कि राम लहर की वजह से सोनिया गांधी का यूपी से एग्जिट हो रहा है। यह तो आपको याद ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों गवार बैठे थे और उन्हें दक्षिण की वायनाड सीट पर जीत मिली थी। कुछ समय पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह जरूर कहा था की अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। लेकिन अब तक कांग्रेस ने राहुल के अमेठी लौटने का कोई संकेत नहीं दिया है। क्या नेहरु गांधी परिवार को उत्तर में कोई सेफ सीट नजर नहीं आ रही है।

1998 में जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली थी। तब भी पार्टी की हालत खराब थी। 1998 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के फौरन बाद उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया था। इसके बाद 1999 में पहली बार कांग्रेस ने सोनिया की अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ा तब कांग्रेस जीती तो नहीं लेकिन सोनिया ने पार्टी के लिए मजबूत कैम्पेनिंग जरूर की थी। 1999 में सोनिया गांधी कैसे फ्रंट से लीड कर रही थी उसे ऐसे समझा जा सकता है कि 1999 में अमेठी जीता और कर्नाटक के बेल्लारी से सुषमा स्वराज को हराया था। साल 2004 आया और वाजपेयी सरकार का इंडिया शाइनिंग का नारा बुरी तरह पिट गया। इसकी कामयाबी का सेहर भी सोनिया गांधी के सिर बंधा। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी की सीट अपने पुत्र राहुल गांधी को दी और 2004 से 2019 के चुनाव तक कांग्रेस हारी या जीती सोनिया गांधी कभी मैदान छोड़ती नजर नहीं आई। इसके पीछे कई कारण राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पिछेल तीन दशक से सत्ता के केंद्र में आने के लिए संघर्षरत कांग्रेस पार्टी 1989 के बाद नेताओं की लंबी फेहरिस्त भी कास्ट पॉलिटिक्स का शिकार हो गई। नतीजा, एक के बाद एक गिरते प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश कांग्रेस हाशिए पर चली गई। अगर कहा जाए कि केंद्र में बदलती सरकारों के समीकरण का सबसे अधिक असर यूपी कांग्रेस पर पड़ा तो गलत नहीं होगा। जब जब केंद्र की राजनीति ने करवट ली तो प्रदेश की राजनीति भी विकास के वादे से दूर जाति आधारित राजनीति पर आकर टिक गई। वीपी सिंह के दौर में 1987 में बोफोर्स घोटाले के आरोप लगाकर कांग्रेस से किनारा करने के बाद से ही पार्टी की प्रदेश में जड़े हिलनी शुरू हो गई। बाद में 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद स्थिति और खस्ता हाल होने लगी। यूपी के विकास पुरुष कहे जाने वाले एनडी तिवारी ने कुछ वक्त के लिए पार्टी से किनारा किया। फिर वापस अपनी पार्टी का इसमें विलय जरूर करा लिया। लेकिन तब तक प्रदेश की राजनीति ने तेजी से करवट लेना शुरू कर दिया। एक तरफ राम लहर पर सवार बीजेपी ने कमंडल के रास्ते अपने रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया। वहीं प्रदेश में तेजी से मजबूत होते क्षत्रप बसपा और सपा ने भी पैर जमाना शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब यूपी में पूरी तरह से कॉस्ट पॉलिटिक्स का उदय हो चुका था। मुलायम सिंह यादव मुस्लिम व यादवों के रहनुमा और मायावती दलित वोटों की रहनुमा बन चुकी थी।

जिस रायबरेली के बारे में कभी शायर मुनव्वर राणा ने कहा था कि ये रायबरेली जनाब यहां राजनीति पनारो से बहती है। वहां से इंदिरा 1967 से 1977 तक सांसद रही। इंदिरा के पति फिरोज गांधी रायबरेली से 1952 और 1957 से चुनाव जीते थे। उस सीट को छोड़ सोनिया गांधी अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा से सांसद जाने का रास्ता चुना है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के रास्ते सांसद जाएंगे राहुल गांधी पहले ही अमेठी से वायानाड की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। राहुल अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं अभी इसपर सस्पेंस जारी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर दिया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

जनक ने उस तोते को दुलार किया जिसका मुख चंद्रमा के समान उज्ज्वल था। वे सुख वे भोजन थे जो व्यास के पुत्र चाहते थे। हल्की हवा उसे दूर नहीं ले गई, मानो वह पहाड़ पर बैठा हो। वह केवल संतुलित, शांत, शांत और प्रसन्नचित्त था बेदाग तोता वहीं खड़ा था मानो ठंडी किरणों से भरा हुआ हो।

तदनन्तर शुकदेव मुनि को आया हुआ देखकर द्वारपालों ने राजा जनक को यह संदेश दिया कि हे राजन्! राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र श्रीशुकदेव जी आपसे मिलने के लिए आये हैं, उन (शुकदेव) मुनि की परीक्षा के लिए महाराज जनक ने अवज्ञापूर्वक मात्र इतना ही कहा कि उनसे कहो कि वे वहीं पर रुकें, इतना कहने के उपरान्त राजा सात दिनों तक पूरी तरह से शान्त रहे।

इसके पश्चात् उन्होंने शुकदेव मुनि को अपने राज-प्राङ्गण में आमन्त्रित किया और वहाँ भी वे सात दिनों तक उसी तरह शान्त रहे। इसके अनन्तर राजा ने उन्हें अपने अन्तःपुर के आँगन में ससम्मान बुलवाया तथा वहाँ पर भी सात दिनों तक वे उनके समक्ष नहीं आये।

विदेहराज जनक ने अन्तःपुर में युवती स्त्रियों, विभिन्न तरह के सुस्वादु पकवान एवं भोज्य पर शुकदेव जी का स्वागत सत्कार किया। वे समस्त भोग एवं भोज्य सामग्री उन व्या को ठीक वैसे ही नहीं डिगा सके, जैसे कि मन्द मन्द प्रवाहित पवन दृढ़तापूर्वक प्रत हुए पर्वत को गतिशील नहीं कर सकता। वहाँ उस अन्तःपुर में ज्ञानी शुकदेव जी असङ्ग, समभाव वाले, निर्मल एवं पूर्णचन्द्र के सदृश प्रतिष्ठित बने रहे। इस प्रकार जब राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के चरित्र की भली-भाँति परीक्षा ले ली, तब उन्हें अपने समीप बुलाया। उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर राजा ने प्रणाम किया और उनका सत्कार किया।

क्रमशः ...

सशस्त्र क्रांति की पहली ज्वाला थे वासुदेव बलवंत फड़के

गौरव काला

देश को आजादी दिलाने में हजारों क्रांतिकारियों ने अपने लहू का कतरा-कतरा बहा दिया। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज 1857 की क्रांति से शुरू हुआ था। लेकिन, पहली क्रांति की विफलता के बाद जब देश के क्रांतिवीर नये तरीके से आजादी की तैयारी कर रहे थे तब तक महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक वीर सपूत जन्म ले चुका था। वो थे- वासुदेव बलवंत फड़के। उन्हें सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ब्रिटिश हूकूमत के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह करने वाले पहले क्रांतिकारी थे बलवंत फड़के। किसानों की दयनीय दशा ने उन्हें विचलित कर दिया था। वो कहते थे कि स्वराज ही इसकी एकमात्र दवा है।

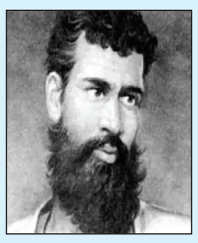

आज वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि है। बलवंत फड़के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। उन्हें आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। वे ब्रिटिश काल में किसानों की दयनीय दशा को देखकर विचलित हो उठे थे। उनका दृढ विश्वास था कि %स्वराज% ही इस रोग की दवा है। उन्होंने ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर हथियार चलाने का अभ्यास किया। उनके नाम से ही अंग्रेज थर-थर कांपते थे। उनके सिर पर 50 हजार रुपये जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा था।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में 4 नवंबर 1845 को जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही कुछ बड़ा करने के सपने देखते थे। उनके पिता ने उन्हें दुकान चलाने को कहा लेकिन, उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मुंबई चले गए। यहां उन्होंने अंग्रेजों के लिए नौकरी की। एक बार बीमार मां को देखने के लिए जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मां को देखने निकल पड़े। मां के निधन ने उन्हें दिल से तोड़ दिया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। भील और धांगड़ जातियों को इकट्ठा किया और रामोशी नाम का क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। 1879 में विद्रोह का आगाज करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति संग्राम में धन एकत्र करने के लिए उन्होंने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटना शुरू किया।

अंग्रेजों के दिल में उनके नाम का इस कदर खौफ था कि वासुलेव बलवंत का नाम सुनकर ही अंग्रेज थर-थर कांपते थे। वो ज्योतिबा पुले और लोकमान्य तिलक के भी साथी थे। वासुदेव बलवंत को सशस्त्र संग्राम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने संगठन के युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार किया।

कहा जाता है कि अंग्रेजों की नाक पर दम कर देने के बाद उनके सिर 50 हजार का ईनाम घोषित हुआ। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी हुआ लेकिन, अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं सके। वो अंग्रेजों के हाथ तब आए जब वो बीमार अवस्था में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उन्हें कालापानी की सजा हुई और इलाज न मिल पाने की वजह से देश का यह वीर सपूत 17 फरवरी 1883 को कालापानी की सजा काटते हुए शहीद हो गया।

भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग के बीच आठवां उम्मीदवार

अजय सेतिया

मंडल की राजनीति वालों के लिए यह सोचने का विषय है कि उनकी राजनीति कमंडल में कैसे जा मिली है। न तो बिहार में मंडल की राजनीति करने वाले लालू यादव का परिवार पिछले 18 साल से अपने बूते पर कभी सत्ता में आ पाया है, न उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार पिछले सात साल से सत्ता में है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दोनों ही राज्यों में पिछड़ों में सबसे बड़ी और ताकतवर जाति यादवों ने पिछड़ी जातियों में सत्ता का बंटवारा नहीं किया। इन दोनों ही राज्यों में मंडल राजनीति वालों ने एमवाई समीकरण को ज्यादा अहमियत दी। यानि मुस्लिम यादव का समीकरण बनाया, जिससे अति पिछड़ी अन्य जातियां सत्ता से ही नहीं, बल्कि आरक्षण के अधिकार से भी वंचित रही।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति के समांतर सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी। गोविन्दाचार्य 1988 में भाजपा के महासचिव बने थे, मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू होना और बाबरी ढांचा टूटने की दोनों घटनाएं उनके महासचिव रहते हुए ही हुई थीं। वह भले ही तमिल मूल के थे, लेकिन उनका बचपन और जवानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बीती, उनकी सारी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। उत्तर प्रदेश और बिहार की जातीय राजनीति को वह अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल इंजीनियरिंग की ऐसी रूपरेखा बनाई, जिसने भले ही देर से, लेकिन अंततः मंडल की राजनीति पर विजय हासिल कर ली। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी से मतभेदों के कारण के.एन. गोविन्दाचार्य को 2000 में भाजपा छोड़नी पड़ी, लेकिन वह भाजपा के भीतर सोशल इंजीनियरिंग का बीज बो गए थे। जब गोविन्दाचार्य पार्टी के महासचिव थे, तभी नरेंद्र मोदी गुजरात से शिफ्ट हो कर पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए थे। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद

नरेंद्र मोदी ने गोविन्दाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग को पार्टी में आगे बढ़ाया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने पार्टी में छोटी छोटी पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों को जोड़ना शुरू किया, जातियों में प्रभाव रखने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करवाने या उनकी पार्टियों को एनडीए में शामिल करवाने की मुहिम चलाई गई। जिसका पहला प्रयोग तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ही हो गया था, 2017 में सोशल इंजीनियरिंग के बूते ही भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई।

जहां भाजपा सभी पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने के बाद संगठन और सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रही है, वहीं बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी अपने ही परिवारों को बढ़ावा देने वाली पार्टियां बन कर रह गई। अभी उत्तर प्रदेश का ताजा उदाहरण ही लेते हैं। अखिलेश यादव बात तो पीडीए यानि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की करते हैं, लेकिन राज्यसभा की तीन सीटों के लिए उन्होंने दो अगड़ी जातियों के नेताओं को और एक दलित नेता को टिकट दिया। वह भी मजबूरी में, क्योंकि पहले मायावती से गठबंधन टूटने और अब जयंत चौधरी के भाजपा के साथ चले जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किसी दलित को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। अखिलेश ने दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले रामजी लाल सुमन को टिकट दिया है, वह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और चार बार के सांसद रहे हैं। उनका आगरा, अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद के दलित समुदाय में अच्छा असर है। 1977, 1989, 1999 और 2004 में वह फिरोजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 और 2019 में हाथरस से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव हारे।

दूसरी तरफ भाजपा ने आसानी से जीतने वाली सात सीटों पर उम्मीदवार तय करते समय सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा। भाजपा ने चार उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से उतारे हैं। पिछड़े वर्ग में कुर्मी, जाट, बिंद और मौर्य को भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस से आए पूर्वांचल के कुर्मी नेता आरपीएन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कुशवाहा, शाक्य, सैनी वोट बैंक को साधने के लिए अमरपाल मौर्य को टिकट दिया है। इसी तरह एक तरफ तो जाट वोट बैंक साधने के लिए जयंत चौधरी से गठबंधन किया गया है, तो दूसरी तरफ मथुरा में जाट कार्ड खेलते हुए भाजपा ने पूर्व सांसद तेजवीर सिंह को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल में बिंद मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी ने संगीता बलवंत बिंद को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है, वैश्य समाज से नवीन जैन को टिकट दिया है, तो ब्राह्मण समाज से सुधांशु त्रिवेदी को ही दोबारा टिकट दिया गया है। इसी तरह चंदौली से राजपूत समाज की साधना सिंह को टिकट दिया गया है। इस तरह ओबीसी और राजपूत वर्ग से दो महिलाएं भी हो गईं। यह है भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग।

विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो भाजपा सात और समाजवादी पार्टी तीन सीटों पर बिना मतदान के ही जीतने की स्थिति में थी। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से जया बच्चन को पांचवी बार और पूर्व आईएएस अफसर आलोक रंजन को टिकट देने से सपा में असंतोष व्याप्त हो गया है, इस असंतोष को देखते हुए भाजपा ने आठवाँ उम्मीदवार उतार दिया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए फर्स्ट प्रिफरेंस के 37 विधायकों की जरूरत है। 403 सदस्यीय विधानसभा में चार सीटें खाली हैं, बाकी 399 सीटों में भाजपा के 252, भाजपा के सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के 13, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के छह और निषाद पार्टी के छह सदस्य हैं। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के 9 विधायक भी जोड़ दें तो कुल संख्या 286 वोट हैं। इस तरह 259 विधायकों की पहली वरीयता से सात उम्मीदवारों की आसान जीत के बाद भाजपा के पास 27 वोट बच जाते हैं। दूसरी तरफ सपा को तीनों उमीदवार जिताने के लिए 111 विधायकों की जरूरत है। सपा के 108 और कांग्रेस के दो सदस्य हैं, उन्हें सिर्फ एक विधायक के फर्स्ट प्रिफरेंस की जरूरत है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के दो और बसपा का एक सदस्य है, इन तीनों में से एक वोट का जुगाड़ करना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की नाराजगी और स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव पद से इस्तीफे ने अखिलेश यादव और सपा का संकट बढ़ा दिया है।

पल्लवी पटेल हालांकि सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्होंने एलान कर दिया है कि वह सपा के राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों से नाखुश हैं। अखिलेश की पीडीए रणनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जया बच्चन और आलोक पीडीए नहीं हैं। उन्होंने सपा उम्मीदवारों को वोट नहीं देने का एलान भी कर दिया है, इससे सपा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर अतीक अहमद का बेटा अब्बास अंसारी सुभासपा का विधायक है, यह पार्टी हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा से जा मिली है। अब्बास अंसारी का वोट समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, इसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी के नौ विधायकों में से भी तीन-चार विधायक आरएलडी के भाजपा से गठबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने आठवाँ उम्मीदवार खड़ा करके उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। संजय सेठ ने आठवें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है।

आज का इतिहास

1878 सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया।
1882 पहला टेस्ट क्रिकेट मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया।
1883 महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव बल वंत फडके का अदन की जेल में निधन हुआ।
1894 अमेरिकी डाकू जॉन वेस्ले हार्डिन को जेल से रिहा किया गया।
1904 इतालवी संगीतकार गियाकोमो पुक्किनी की मैडम बटरफ्लाई का मिलान में ला स्काला में प्रीमियर हुआ, जिससे नकारात्मक समीक्षा हुई जिसने उन्हें ओपेरा को फिर से लिखने के लिए मजबूर किया।
1913 न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी नेशनल गार्ड की 69 वीं रेजीमेंट आर्मरी में, आर्मरी शो खोला गया, जिसमें अमेरिकियों को अवेंट-गार्डे और ऑर्मोडर्न आर्ट से परिचित कराया गया।
1927 हवाई जहाज बनाने वाली विश्व की प्रथम कंपनी की स्थापना विलियम बोइंग और एल्बर्ट हबार्ड द्वारा की गयी।
1933 अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका 'न्यूजवीक' प्रकाशित हुई।
1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनीवेटोक का युद्ध शुरू हुआ जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने जीत हासिल की।
1947 सोवियत संघ में 'वायस ऑफ अमेरिका' का प्रसारण शुरू किया गया।
1949 चैम वीज़मैन ने इज़राइल के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया।
1959 क्लाउड कवर वितरण को मापने के लिए पहला मौसम उपग्रह, वानगार्ड 2 लॉन्च किया गया था।
1962 जर्मनी के हैम्बर्ग में तूफान से 265 लोगों की मौत हुई।
1964 गैबोन के सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति लोन एम बा को उखाड़ फेंका, लेकिन फ्राँस ने 1960 की संधि का सम्मान करते हुए, अगले दिन M'ba को जबरन बहाल कर दिया।
1978 द ट्रिबल्स-अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट के पास ला मोन रेस्तरां में गर्भपात किया।
1995 कॉलिन फर्ग्यूसन को NY में LIRR पर 6 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया।
1997 पासाडेना कैलिफोर्निया में कार्ल सागन पब्लिक मेमोरियल का उद्घाटन किया गया।
1998 एंथ्रेक्स के कब्जे के लिए लैरी वेन हैरिस और बिल लेविट को गिरफ्तार किया गया।

क्या मोदी सरकार किसान विरोधी है?

अनिल तिवारी

करीब दो वर्ष पहले किसानों ने जब दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था, तब कई महीने तक प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और किसान वापस लौट गए। मगर अब एक बार फिर कई मुद्दों के साथ किसानों ने %दिल्ली चलो% के नारे के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी किसानों ने आज 15 फरवरी को रेल रोको तथा 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए जिन ताकतों ने पूर्व में ऐसे हठधर्मी आंदोलन का समर्थन किया था, वही तत्व आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर आंदोलन को हवा दे रहे हैं।

गौरतलब है कि दो वर्ष पहले किसानों के आंदोलन के बाद केंद्र की मोदी सरकार को संसद से पारित तीन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। तब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी देने का वादा किया था। मगर बड़े किसानों की शिकायत है कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए थे तब किसानों को उनसे भारी उम्मीद थी। किसानों को लग रहा था कि उनकी शाश्वत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन दो-तीन साल बीतते ही किसानों के आंदोलन सड़क पर प्रकट होने लगे। आंदोलन स्वाभाविक थे या प्रायोजित यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसके आधार पर मोदी सरकार के बारे में धारणा बनने लगी या बनाई जाने लगी कि वह किसान विरोधी हैं। क्या वास्तव में मोदी सरकार किसान विरोधी है? मोटे तौर पर मोदी सरकार की कृषि नीति तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीति से प्रेरित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना, पशुपालन जैसे कृषि संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश बढ़ाना, कृषि को बाजार से जोड़ना, गांव में बुनियादी ढांचे की मजबूती प्रदान करना।

इसके लिए पहले आवश्यक कार्य था कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाना। यहां मोदी सरकार के आलोचकों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि मोदी राज में कुल बजट में कृषि क्षेत्र का हिस्सा पूर्व की सरकारों से अधिक है। हालांकि यह कृषि पर आधारित आबादी की तुलना में अभी भी बहुत कम है। कृषि क्षेत्र की ही तरह सरकार ने ग्रामीण ढांचे को मजबूती प्रदान करने पर भी जोर दिया ताकि आर्थिक मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारा जा सके। सरकार की यह रणनीति कारगर होती दिख रही है। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में जो मंदी के लक्षण दिखने लगे थे, उसमें अब बहुत सुधार हुआ है। आंदोलनकारी किसान एमएसपी के साथ ऋण माफी की भी मांग कर रहे हैं। कर्ज माफी किसानों की समस्या का समुचित समाधान नहीं है। अगर ऐसा होता जैसा कि मनमोहन सरकार के समय किया गया था, तो इसकी दोबारा मांग ही नहीं उठानी चाहिए थी। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना ही उनकी समस्या का वास्तविक समाधान है।

मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और किसानों पर गठित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल कर दी। हालांकि सरकार के फार्मूले को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना करती रहीं लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार इस आयोग की रिपोर्ट पर आठ साल चुप रही और एमएसपी देने की पहल ही नहीं की थी। यहां असली चुनौती एमएसपी की घोषणा नहीं बल्कि उसे व्यवहार में सुनिश्चित करने की है। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 6त्न किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है यानी बाकी किसान आज भी औने-पौने दाम पर अपना अनाज बिचौलियों को बेचने पर मजबूर रहते हैं। एमएसपी को लेकर हर साल भले ही शोर मचता हो लेकिन हकीकत यही है कि एमएसपी का लाभ उठाने में हरियाणा और पंजाब के किसान ही सबसे आगे हैं। साल 2016 की नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब का हर किसान एमएसपी पर ही फसल बेचता है, यानी छह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत में पंजाब की हिस्सेदारी 100त्न है।

रबी सीजन में गेहूं पर एमएसपी का लाभ लेने वाले 42त्न से ज्यादा किसान केवल पंजाब और हरियाणा से थे। पंजाब में लगभग 2000 मंडियां हैं। ऐसी व्यवस्था देश में तो क्या दुनिया में भी शायद ही कहीं हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जब तीन नए कृषि कानून लेकर आई थी तब मंडी के कारोबारियों और आढ़तियों ने अपने अस्तित्व पर संकट देख किसान आंदोलन का तड़का लगाया था।

एमएसपी को लेकर सरकार के सामने बजट का एक व्यवहारिक संकट भी है क्योंकि एमएसपी लागू होते ही बजट का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित करना होगा, जिसका बोझ सरकार पर ही पड़ेगा। अभी फिलहाल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। मौजूदा रेट के हिसाब से सरकार सभी फसलें खरीदती हैं तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका खर्च 18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। खाद और सब्सिडी के 2 लाख करोड़ रूपया अलग से यानी कुल मिलाकर लगभग 20 लाख करोड रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसकी भरपाई कहां से होगी?

जाहिर सी बात है टैक्स बढ़ाकर। लेकिन यह मामूली टैक्स बढ़ोतरी से पूरा होने वाला नहीं है, इसके लिए कई गुना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो निवेश से लेकर निर्यात तक पर नकारात्मक असर दिख सकता है। निजी कारोबारियों पर एमएसपी पर खरीद की शक्ति बढ़ेगी तो वह भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव गिरने पर आयात करना शुरू कर सकते हैं, जिससे घरेलू बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। समस्या भंडारण की भी है। सरकार अगर सारी फसल खरीद लेगी तो रखेगी कहां? वर्तमान सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का नेटवर्क खड़ा करके ग्रामीण कृषि मंडियों को उनसे जोड़ने की कोशिश की। तीन नए कृषि कानून लाकर देश के सभी छोटे-बड़े किसानों को लाभ पहुंचाने का खाका तैयार किया जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसानों के भारी विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था। अब किसानों के ताजा आंदोलन के बाद फिर जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर उसे लेकर सही नीति नहीं अपनाई गई तो अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है।

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ताजा प्रदर्शन के जरिए वे सरकार को दो वर्ष पहले किए गए उन वादों को याद दिलाना चाहते हैं, जो आंदोलन को वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने किए थे। वे वादे अब तक पूरे नहीं हुए। वहीं सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है। प्रश्न है कि वादा करने के बावजूद सरकार आखिर अब तक क्या कर रही थी कि इस मसले पर किसानों के बीच स्पष्टता नहीं बन सकी? हालांकि विरोध प्रदर्शन से उपजने वाली अव्यवस्था की आशंका के मद्देनजर सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसान संगठन अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं, तो उन्हें बाधित क्यों किया जाना चाहिए?

2020 के आंदोलन से कैसे अलग है किसानों का दिल्ली चलो मार्च

अंकित सिंह

फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों पर दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद, पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार सुबह अपना %दिल्ली चलो% मार्च शुरू किया था। किसानों की ओर से आंदोलन को फिर से जीवित किया जा रहा है जो 2021 में केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद खत्म हो गया था। वह आंदोलन लगभग एक साल तक चला था। भारतीय किसान संघ (बीकेयू), जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा है, ने किसानों की कई अधूरी मांगों का हवाला देते हुए शुक्रवार, 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकार के साथ बातचीत के बाद भी किसानों के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि, यह बात भी सच है कि इस बार किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। 2020 में, किसानों ने तीन कृषि कानूनों का विरोध किया, जिसके कारण 2021 में उन्हें निरस्त कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले को लागू करने, कर्ज माफी, पेंशन और पिछले विरोध के मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया गया है। 2020 के विपरीत, किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कंटीले तारों, सीमेंट बैरिकेड्स और बाधाओं सहित सख्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और राज्यों के बीच की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस बार किसानों के दिल्ली से दूर ही रोकने की कोशिश है। 2020 में वे दिल्ली में दाखिल हो चुके थे। इस बार दिल्ली चलो मार्च से पहले किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। इस बार किसान संगठनों ने दिल्ली चलो मार्च का भी आह्वान किया है। पिछली दफा आत्महत्या, खराब मौसम और कोविड-19 के कारण दर्जनों किसानों की मौत हो गई थी। प्रमुख कृषि नेताओं, जिन्होंने 2020-21 में किसानों के विरोध का नेतृत्व किया था, ने इस साल आंदोलन से खुद को दूर कर लिया है। पिछले संयुक्त किसान मोर्चा से बना संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) पिछले तीन दिनों से पंजाब और हरियाणा में किसान विरोध 2.0 को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। योगेन्द्र यादव, जोगिंदर सिंह उगराहां, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चादुनी, बलबीर सिंह राजेवाल, मंजीत राय, डॉ. दर्शन पाल, शिव कुमार कक्का और डॉ वीएम सिंह जैसे दिग्गज इस बार नदारद हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर और भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल इसका नेतृत्व करते दिख रहे हैं।

अरब जगत की असाधारण घटना है यूएई में मंदिर निर्माण

संजय तिवारी

यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि अरब भूमि के एक हिस्से आबू धाबी में इतने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए जिसमें मूर्तिपूजा होती हो। यह असाधारण घटना है दुनिया के लिए भी और अरब जगत के लिए भी। अरब की भूमि से मूर्तिपूजा सदियों पहले समाप्त हो गयी थी जब वहां इस्लाम का उदय हुआ। इतिहास में तो ठीक ठीक इसका उल्लेख नहीं मिलता कि छठी शताब्दी में वास्तविक रूप से मक्का में क्या हुआ था लेकिन इस्लामिक किताबें इस बारे में खुलकर बताती हैं।

इस्लामिक किताबों में इस्लाम की बुनियाद ही यही बतायी गयी कि उनके पैगंबर ने मक्का में 360 बुतों (मूर्तियों) को तोड़कर इस्लाम की नींव डाली थी। इस्लामिक किताबों के अनुसार पैगंबर ने एक अल्लाह की उपासना का संदेश दिया था जिसे मुसलमान बिना किसी शक शुबहा के मानता है। अगर हम इस्लामिक किताबों के हवाले को ही इतिहास मान लें तो 1450 साल बाद इतने भव्य तरीके से अरब की धरती पर मूर्तियों या बुतों की फिर से वापसी हुई है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में श्रीस्वामीनारायण मंदिर, आबूधाबी का लोकार्पण एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसे भारतीय उपहाद्वीप के मुसलमान ही शायद स्वीकार नहीं कर पायेंगे। इस्लाम को लेकर उनकी बुनियादी समझ यही है कि इस्लाम में मूर्तिपूजा नहीं होती। अरब की धरती से यही संदेश पूरी दुनिया में फैलाया गया लेकिन अब उसी अरब के एक हिस्से यूएई के आबूधाबी में मूर्तियों से भरा मंदिर बनकर तैयार हो गया है।

1450 साल पहले अरब के लोग भी मूर्तिपूजक ही थे। हर कबीले का अपना देवी या देवता होता था और देवी देवताओं को जहां रखा जाता था उसे काबा कहते थे। काबा एक प्रकार से मंदिर का ही रूप हुआ करता था। वहीं पर लोग अपनी अपनी आस्था का पत्थर रखकर पूजा पाठ या बलि आदि देते थे। एक दूसरे की आस्था को लेकर कोई टकराव नहीं था। लेकिन इस्लाम के उदय के बाद हर प्रकार के बुत तोड़ दिये गये और एक अल्लाह की इबादत को ही सही बताया गया। मक्का स्थित काबा में सिर्फ हजर ए असवद नामक पत्थर को छोड़कर बाकी सारे पत्थर हटा दिये गए। यह इस्लामिक इतिहास है।

दुबई और शारजाह पहले से प्रवासी भारतीयों के लिए खुले थे इसलिए सबसे पहला प्रभाव वहीं दिखा। दुबई में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो आज भी मौजूद है। दुबई में ही अभी एक साल पहले एक और मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही दुबई में गुरुद्वारे और चर्च के लिए भी जगह दी गयी ताकि वो अपने अपने पूजाघर बना सके। 2016 में एक सहिष्णुता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेन्स) बनाया गया ताकि यूएई के लोगों में दूसरे धर्म और मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता विकसित की जा सके। वर्तमान में इसके मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक हैं जो यूएई के फाउण्डर शेख जायेद के खानदान से ताल्लुक रखते हैं।

इन्हीं शेख नहयान के प्रयासों का परिणाम है कि आबूधाबी में स्वामीनारायण मंदिर को पहले 2.5 एकड़, फिर 5 एकड़ और अंत में 13.5 एकड़ जमीन दी गयी ताकि वो वहां पर मंदिर बना सकें। लेकिन यूएई की धरती पर मंदिर का निर्माण मात्र जमीन आवंटन का मसला नहीं था। उसके पहले उन्हें अपने दिलों में यह जगह देनी थी कि कोई दूसरा अगर उनके अल्लाह के अलावा किसी और भगवान की पूजा करना चाहता है, तो वह कर सकता है। यह जगह मिली तो यूएई में मस्जिद के साथ ही मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा सबके लिए जगह आवंटित कर दी गयी।

यूएई के बाद अब बहरीन भी इसी रास्ते पर है। बहरीन ने भी स्वामीनारायण संप्रदाय को मंदिर बनाने के लिए जगह प्रदान कर दी है और जल्द ही अरब जगत में स्वामीनारायण का दूसरा मंदिर बनना शुरु होगा। दूसरी ओर सऊदी अरब ने अभी तक दूसरे धर्म के पूजास्थलों के लिए अपने दरवाजे तो नहीं खोले हैं लेकिन जिस तरह के सामाजिक सुधार वहां हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि निकट भविष्य में सऊदी अरब के दरवाजे भी मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे के लिए खुलेंगे। अभी भी सऊदी अरब में अपना धर्म मानने की मनाही तो नहीं है लेकिन ऐसा सिर्फ आप अपने घर के भीतर कर सकते हैं। वहां न तो सार्वजनिक मंदिर बन सकता है और न ही चर्च। लेकिन आज यूएई जिस बात को समझ रहा है उसी दिशा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को लगता है कि तेल संपदा खत्म होने से पहले अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक उदार, सहिष्णु और आधुनिक समाज के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि लोगों की आवाजाही और पूंजी निवेश से भविष्य में भी उनकी संपन्नता बरकरार रह सके। इसके लिए वो अपने उन शासकीय नियमों में सुधार कर रहे हैं जिन पर इस्लाम की गहरी छाप है। वो इसे सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित रखना चाहते हैं वह भी बहुत लचीले रूप में। इसलिए सऊदी अरब ने कम उम्र के बच्चों को मस्जिद मदरसों से दूर करके उन्हें आधुनिक स्कूलों का रास्ता दिखाना शुरु किया है।

आबूधाबी में भव्य मंदिर का निर्माण जितना हिन्दू गौरव की बात है उससे अधिक इस्लामिक टॉलरेन्स की बात है जिसकी शुरुआत अरब से ही हो रही है। देर सबेर इसका असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होगा और उन तक यह संदेश जाएगा कि सहअस्तित्व और बहुदेववाद से ही धरती पर सद्भाव भरा जीवन संभव है। किसी भी प्रकार का एकमतवाद धरती पर सभ्यताओं के बीच सिर्फ दुश्मनी और टकराव ही पैदा करेगा। भविष्य की वह दुनिया जहां साइंस भी एक रिलीजन के तौर पर स्थापित हो जाएगा, उसमें किस्से कहानियों पर आधारित एकमतवाद के लिए वैसे भी कोई जगह नहीं रह जाएगी।

बहुदेववादी सहअस्तित्व की जो शुरुआत आबूधाबी से हुई है वह अब रुकेगी नहीं। इसीलिए आबूधाबी में स्वामीनारायण मंदिर के सामने एक डिवाईन आई बनायी गयी है। मंदिर में प्रवेश से पहले उस डिवाइन आई से मंदिर का दर्शन करना होगा जिसकी दीवारों पर अलग अलग भाषाओं में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा है- सद्भाव। सब जीवों के प्रति यही सद्भाव सनातन हिन्दू धर्म का मूल संदेश है जो आबूधाबी के स्वामीनारायण मंदिर से समस्त संसार में प्रसारित होगा। इस सद्भाव का जन्म सहिष्णुता या टॉलरेन्स से ही संभव है, जिसके लिए अलग मंत्रालय बनाकर यूएई अपनी पहल कर चुका है। अब बाकी इस्लामिक देशों को देर सबेर इस दिशा में ही आगे बढ़ना है।

लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला

विराग गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। पिछले छह वर्षों में इस योजना से 16 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा धन सभी पार्टियों को मिला है। नोटबंदी के बाद तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017 के वित्त विधेयक के माध्यम से इस योजना को पेश किया था। उसके लिए रिजर्व बैंक, आयकर, कंपनी, जनप्रतिनिधित्व और विदेशी चंदों से जुड़े कई कानूनों में बदलाव भी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद इस योजना के साथ सारे कानूनी बदलाव भी निरस्त हो गए हैं।

चुनावी बॉन्ड लागू होने से पहले पार्टियों को लगभग 81 फीसदी रकम अज्ञात स्रोतों से मिलती थी। जेटली ने दलील दी थी कि चुनावी बॉन्डों से पार्टियों की फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने के साथ काले धन पर अंकुश लगेगा। पुरानी कानूनी व्यवस्था के अनुसार, कंपनियां सालाना मुनाफे की अधिकतम सीमा के अनुसार ही दान दे सकती थीं। लेकिन कानून में बदलाव के बाद घाटे वाली कंपनियां भी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा देने की हकदार हो गईं। मतदाताओं और पार्टियों को चुनावी बॉन्ड देने वाले की जानकारी नहीं मिल सकती थी। लेकिन सरकार को स्टेट बैंक के माध्यम से ये सारी जानकारियां हासिल थीं। कहा जा रहा था कि निजी कंपनियां और कॉरपोरेट्स चुनावी बॉन्ड में पैसा लगाकर सरकारों से अपने हित में अनुचित काम कराते हैं।

ऐसे अनेक कानूनी और सांविधानिक बिंदुओं पर इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन लोकतंत्र से जुड़े इस बड़े मामले की सुनवाई और फैसला आने में सात साल लग गए। सॉलिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल ने इस योजना का अनेक तरीके से बचाव करने की कोशिश की। सरकारी दलीलों के अनुसार, वोटरों को ऐसे चंदे के बारे में जानने का कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे बॉन्ड और विदेशों से मिल रहे चंदे पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। रिजर्व बैंक ने भी इन बॉन्डों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग होने की आशंका जाहिर की थी। केंद्र और राज्य सरकारों को चुनावी बॉन्ड में विशेष बढ़त मिलती है, इसलिए इस योजना को जजों ने समानता के विरुद्ध माना है।

भारत में लॉबिंग गैर-कानूनी है, लेकिन चुनावी बॉन्डों के माध्यम से निजी कंपनियां सरकारों से अनुचित लाभ ले रही हैं। इस बात को सरकार ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार किया। सरकारी वकील के अनुसार, चुनावी चंदे का खुलासा होने से चंदा देने वाली कंपनियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ सकता है। जो लोग चुनावी बॉन्ड से सिर्फ भाजपा को फायदा होने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक राज्य में सरकार चलाने वाली टीएमसी को लगभग दस फीसदी फंडिंग मिली है। इसलिए अगले महीने चुनावी बॉन्ड का हिसाब-किताब सार्वजनिक होने पर लोकसभा चुनावों के पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। इस योजना के रद्द होने के बाद पुराने तरीकों से पार्टियों को फंडिंग जुटानी होगी। कानून के अनुसार, 20 हजार रुपये से कम की रकम गुमनाम तरीके से ली जा सकती है। पार्टियों को चेक के माध्यम से कंपनियों से चंदा मिल सके, इसके लिए आयकर विभाग ने वर्ष 2013 में ट्रस्ट की व्यवस्था बनाई थी। अनुमानों के अनुसार, पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। नियमों का उल्लंघन करके प्रत्याशी बड़े पैमाने पर काले धन का चुनावों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, सभी पार्टियों को कानूनी और गैर-कानूनी तरीके से चंदा मिलता है। पार्टियों के संगठित पैसे से कॉरपोरेट ऑफिस, चार्टर्ड फ्लाइट, रोड शो, रैलियां और नेताओं की खरीद-फरोख्त भी होती है। 30 साल पहले बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में नेता, अपराधी और कॉरपोरेट्स की मिलीभगत को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट माना गया था। वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में सरकार की तरफ से चुनावी खर्च देने की बात कही गई थी। विधि आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग ने चुनावी कानून दुरुस्त करने के लिए कई रिपोर्टें दी हैं। ऐसी सभी कमेटियों में हुए विमर्श को धता बताकर नेता चुनावों में काले धन का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं।

चुनावों में टिकट पाने के लिए हाय-तौबा मचाने और सरकार बनाने में रिसोर्ट पॉलिटिक्स से साफ है कि राजनीति सबसे बड़ा व्यापार है, जहां सफल होने के लिए आपराधिक तरीके से काले धन का निवेश होता है। सीबीआई और ईडी के छापों से साफ है कि नेताओं के संरक्षण में खनन, शिक्षा, रियल एस्टेट और नौकरी में माफिया सक्रिय और प्रभावी हैं। दिवालिया कानून की आड़ में अनेक कंपनियां सरकारी बैंकों का पैसा हजम कर रही हैं। ऐसी कंपनियों को चुनावी बॉन्ड की आड़ में फंडिंग की इजाजत देना देश के खजाने की लूट ही मानी जाएगी। विपक्ष में रहकर सभी पार्टियां चुनावी व्यवस्था को ठीक करने की बात करती हैं, लेकिन काले धन के बाहुल्य से सरकार बनाने की होड़ में शुचिता के संकल्प तिरोहित हो जाते हैं। नेताओं को चुनाव जीतने के बाद गाड़ी, बंगला और अनेक सुविधाएं मिलती हैं। पार्टियों के चंदे और आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता और उन्हें बेशकीमती सरकारी जमीन पर ऑफिस बनाने की सहूलियत मिलती है। चुनाव आयोग और आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, कई रजिस्टर्ड पार्टियां मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में लिप्त हैं। संविधान में जनता के शासन को मान्यता मिली है, लेकिन इस सांविधानिक व्यवस्था को पार्टियों ने अपहृत कर लिया है। चुनावों में काले धन के कैंसर को खत्म करके ही राजनीति में अपराध और सरकारों में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सकता है। हम यूरोप और अमेरिका के विकास मॉडल का अनुकरण करते हैं।

सिर्फ नाम और नारा देकर बिखरने वाला इंडिया गठबंधन

नीरज कुमार दुबे

विपक्षी दलों ने इंडिया नामक गठबंधन बना कर नारा दिया था कि जीतेगा इंडिया। विपक्षी दलों ने केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरते हुए कहा था कि हम 400 सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारेंगे ताकि भाजपा को हराया जा सके। विपक्षी दलों ने दावा किया था कि हम सीट बंटवारे के समय बड़ा दिल दिखाएंगे। लेकिन यह सब दावे तब हवा हवाई हो गये जब यह गठबंधन ही भरभरा कर गिर गया। पहले तो इस गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही पलटी मार कर वापस एनडीए के पाले में चले गये। फिर राष्ट्रीय लोक दल ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस गठबंधन से किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार भी घोषित करने शुरू कर दिये।

अब जम्मू-कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने भी ऐलान कर दिया है कि वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने बलबूते लड़ेगी। हम आपको बता दें कि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने के प्रयास तो भरसक किये लेकिन आपसी विश्वास की कमी से यह गठजोड़ हमेशा बिखरता चला गया। याद कीजिये जब राष्ट्रपति चुनाव की बात आई थी तब भी विपक्ष एकजुट हुआ था लेकिन ऐन मौके पर सारे बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गये थे और यशवंत सिन्हा को आगे कर दिया था। ऐसा ही हाल उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था जब विपक्षी एकजुटता ऐन चुनाव से पहले बिखर गयी और कोई सशक्त उम्मीदवार देने की बजाय पूर्व राज्यपाल मारग्रेट अल्वा को मैदान में उतार दिया गया था।

यही हाल लोकसभा चुनावों से पहले भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री पद के अलावा गठबंधन के संयोजक के पद के लिए भी इतने दावेदार थे कि बात बन ही नहीं पाई। यह गठबंधन सिर्फ नाम और नारा तय करने के बाद ही बिखर गया। देखा जाये तो यह भारतीय राजनीति में सबसे विफल प्रयोग था क्योंकि इससे पहले बनने वाले गठबंधनों ने कुछ महीनों और सालों तक की जिंदगी जी लेकिन इंडिया गठबंधन तो मात्र तीन बैठकों के बाद ही टांय टांय फिस्स हो गया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक प्रमुख पार्टी राकांपा भी टूट चुकी है और इसका बड़ा भाग एनडीए के खाते में जबकि छोटा टुकड़ा विपक्ष के पास बचा है। इसके अलावा चुनाव सिर पर होने के बावजूद राहुल गांधी को दिल्ली में सीट बंटवारे पर चर्चा करने की बजाय दूसरे प्रदेशों में घूमते देख फारुक अब्दुल्ला का माथा भी ठनक गया है और उन्होंने भी इस गठबंधन से किनारा कर लिया है। देखना होगा कि इस गठजोड़ में बचे खुचे दल भी चुनाव घोषणा तक साथ रहते हैं या जल्द ही किनारा करते हुए कांग्रेस को अकेला छोड़ देते हैं। फिलहाल तो इस गठबंधन के बचे हुए घटक दल एक दूसरे से %तू चल मैं आया% कहते दिख रहे हैं। यही नहीं, हाल के दिनों में कांग्रेस के ही कई बड़े नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं और कई नेता किनारा करने की तैयारी में हैं। इससे इंडिया गठबंधन के बचे हुए घटक दलों में यह भी संदेश जा रहा है कि जो पार्टी खुद एकजुट नहीं है वह विपक्षी दलों को कैसे एकजुट रख पायेगी?

अपनी रुचि को करियर के रूप अगर हम चुनें तो उसमें हम सफल भी हो सकते हैं। कई युवा की रुचि मूर्ति कला में होती है। मूर्तिकला शिल्प की एक प्राचीन विधा है। मूर्तिकार अपनी कल्पना को साकार रूप देकर एक सुंदर कृति बनाता है।

मूर्तिकला एक करियर अवसर भी है। युवा इसे अपनी रुचि अनुसार करियर के रूप में चुन सकते हैं। वर्तमान में लोगों की रुचि मूर्ति कला की तरफ भी हो रही है। आजकल सीमेंट-क्रांकीट, सफेद तांबा, प्लास्टर ऑफ पेरिस व मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं।

रेत पर भी सुंदर कृतियां उकेरी जाती है जिसे सैंड आर्ट कहते हैं। हमारे देश के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने इस कला के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। इसके अलावा मोम की प्रतिमाएं भी बनने लगी हैं।

मैडम तुस्साद और लंदन में उनका संग्रहालय पूरे विश्व में मशहूर है जिनमें हर क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों की मोम की प्रतिमाएं बनी हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी मूर्तिकारों के लिए रोजगारों के असीमित अवसर उपलब्ध हैं।

50 प्रश अकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री ली जा सकती है। एप्टिट्यूड टेस्ट में सफल होने के बाद ?डिग्री कोर्स में प्रवेश मिलता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री के बाद मास्टर डिग्री भी की जा सकती है। पर इसके लिए बैचलर डिग्री में 50 प्रश अंक जरूरी है।

मूर्तिकला का डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है, जो अनेक संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। मूर्तिकला में एक्सपर्ट बन आप गवर्नमेंट अथवा प्राइवेल स्कूल में क्राफ्ट टीचर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

विभिन्न संग्रहालयों में मूर्तियों के रखरखाव के लिए मूर्तिकारों को रखा जाता है। प्रसिद्धि मिलने पर स्वयं मूर्तियां बनाकर और बेचकर स्वयं का बिजनेस भी किया जा सकता है। आर्ट गैलरी भी खोल सकते हैं।

इन संस्थानों से आफ फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं-

- जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई।
- विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल।
- कॉलेज ऑफ आर्ट, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।

ऑफिस का पहला दिन है जरा बरतें एहतियात

हर एक युवा के लिए उसकी पहली नौकरी बेहद खास होती है। कॉलेज शिक्षा खत्म करने के बाद जब कॉलेज प्लेसमेंट या प्रयासों से आप किसी कंपनी में नौकरी पाते हैं तो आपको नौकरी मिलने की खुशी के साथ-साथ नौकरी के पहले दिन की भी चिंता सताती है। ऑफिस में अपने पहले दिन को लेकर आपके मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं। कुछ सवाल बेहद आम होते हैं, जैसे अगर मैं पहले ही दिन ऑफिस के सभी लोगों के नाम याद नहीं कर पाया तो ऑफिस के साथियों को क्या बुरा लगेगा? या पहले एसाइनमेंट के लिए मुझे कब बुलाया जाएगा? या क्या मैं घर से लंच ले जा सकता हूं? इन सवालों का कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंपनी की अपनी अलग कार्य संस्कृति होती है। फिर भी कुछ बातें हैं, जिन्हें पहली नौकरी के पहले दिन याद रखा जाना चाहिए।

सजग रहें

आप ऑफिस में नए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आपके काम और व्यवहार पर सभी की नजरें हों। इसलिए आपसे जो कहा जाए, उसे ध्यान से सुनें और काम को लेकर उतावलापन न दिखाएं। काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करें।

उत्साह

आपके काम करने के तरीके और कार्यकुशलता को परखने के लिए आपको कुछ ऐसे काम भी दिए जा सकते हैं, जिनमें आपकी रुचि कम हो। फिर भी उस काम को खुशी से अपने हाथ में लेकर अच्छे से करने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने सीनियर की भी मदद ले सकते हैं। ऐसा करने से सीनियर के बीच आपकी छवि उत्साही कर्मचारी की बनेगी।

रुचि

कई बार ऑफिस के पहले ही दिन आपकी जिम्मेदारियां तय कर दी जाती हैं। काम नया होने की वजह से कुछ मुश्किलें भी पेश आएंगी और घबराहट भी होगी, मगर आपको सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनका निदान तलाशना होगा। यह काम आसानी से हो जाएगा, अगर आप उसमें अपने पसंदीदा काम की तरह रुचि लेना शुरू कर दें।

हर काम करने की न करें कोशिश

ऑफिस के साथियों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके हर काम में खुद से मदद देने के लिए तैयार हो जाना सही नहीं है। खासकर उन कामों में, जिनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। इससे होगा यह कि आप ठीक से काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे और साथियों की नजर में अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगे।

जानें ऑफिस सुविधाएं

ऑफिस आने-जाने का समय, कंप्यूटर सिस्टम कोड, अपनी पोशाक (फॉर्मल/ इन्फॉर्मल), ब्रेकरूम और पार्किंग के बारे में संबंधित विभाग से जानकारी हासिल कर लें।

विभागों को जानें

किसी सहयोगी कर्मचारी के साथ जाकर कंपनी के पूरे कैंपस और बिल्डिंग को देखें। इससे आपको कंपनी के सभी विभागों और उनकी जगह का पता लग जाएगा। मसलन फाइनेंस, मार्केटिंग, लीगल सेक्शन व एचआर डिपार्टमेंट जैसे विभाग और कैफेटेरिया कहां है।

पुराने कर्मियों पर दें ध्यान

ऑफिस की कार्य संस्कृति को समझने के लिए वहां के पुराने कर्मचारियों के कार्य व्यवहार पर गौर करें, जैसे उनका आना-जाना कब हो रहा है? या वह अपनी-अपनी डेस्क पर खाना खाते हैं या साथ बैठ कर?

अंत तक रुकें

कोशिश करें कि अन्य कर्मचारियों के जाने के बाद आप ऑफिस से निकलें। इससे आपको ऑफिस के लोगों के काम करने के तौर-तरीकों को जानने का भरपूर मौका मिलेगा।

उतावलेपन से बचें

नई चीजों को जानने की ललक और रुचि का होना अच्छी बात है, मगर एक सीमा से आगे ये चीजें आपकी छवि और करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कई बार कुछ जानने के उतावलेपन में आप अपने सीनियर से कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, जिससे आपकी अपरिपक्वता दिख जाती है। इससे सीनियर के मन में आपकी छवि अपरिपक्व और अगंभीर कर्मचारी की बन जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सवाल ही न पूछें। सवाल पूछिए, मगर सोच-समझ कर।

● **प्रसन्न प्रांजल**

सेहत से संवारें कैरियर

भारत में योग का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है, बावजूद इसके करियर के लिहाज से इस क्षेत्र में तेजी हालिया वर्षों में ही देखने को मिली है। योग किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके स्वास्थ्य के ऊंचे मानकों को हासिल करने और अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सेहत पर ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होता है।

हमारी मौजूदा तनावपूर्ण जीवनशैली हमें हमेशा तनाव के एक नए स्तर की ओर धकेल रही है। यही वजह भी है कि एक योग्य योग चिकित्सक की मांग इन दिनों खूब बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने वाले पाठय़क्रमों के विकल्प भी पहले से कहीं अधिक मौजूद हैं।

आज सेहत के लिए सजग कई युवा रोगों से मुक्त करने की योग की ताकत को समझते हुए इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जहां एक तरफ दुनिया योग की ताकत को पहचान रही है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्कूल और कॉलेजों में प्रशिक्षक या काउंसलर, चिकित्सा केंद्रों और अस्पताल आदि में योग प्रशिक्षकों या इंस्ट्रक्टर्स को रोजगार की नई राहें दिखाई दे रही हैं। देशभर में कई योग संस्थान योग चिकित्सा में विभिन्न पाठय़क्रम और डिग्री मुहैया करा रहे हैं। योग में मुख्य तौर पर करियर के दो विकल्प हो सकते हैं, पहला शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में और दूसरा योग चिकित्सक के रूप में।

वेतन

अगर आप एक स्वतंत्र योग प्रशिक्षक हैं तो आपकी आय मुख्य तौर पर आपके क्लाइंट्स की संख्या और आपकी फीस पर निर्भर करती है। शुरुआती दौर में कोई भी प्रशिक्षक एक सत्र के लिए 400 से 500 रुपये प्रतिदिन (20 हजार रुपये प्रति माह) का शुल्क प्राप्त कर सकता है। मध्यम स्तर के प्रशिक्षक प्रति माह 40 हजार से 50 हजार रुपये व वरिष्ठ प्रशिक्षक, जो पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, तकरीबन 1 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं।

कौशल एवं योग्यताएं

- इस क्षेत्र में आपकी अच्छी दिलचस्पी होनी चाहिए
- एक अच्छे संस्थान से प्रशिक्षण हासिल करना
- दृढ़ इच्छा-शक्ति
- अच्छी सहनशीलता
- आप जो पढ़ रहे हैं, उसकी सही जानकारी
- आपकी गलतियों से क्लाइंट्स की सेहत और स्वास्थ्य, दोनों को हानि हो सकती है

नफा-नुकसान

काम का कम तनाव
अगर आफ एक फ्रीलांसर हैं तो आप अपनी पसंद से काम का समय तय कर सकते हैं
आप खुद को सेहतमंद बनाते हुए कमा भी सकते हैं
आय कम-ज्यादा हो सकती है
संस्थान एवं उनकी वेबसाइट्स
मोरारजी देसाई नैशनल इंस्टीटयूट ऑफ योगा, नई दिल्ली

दिनचर्या

- सुबह 5.30 बजेः सुबह उठ कर प्राणायाम और ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना
- सुबह 8 बजेः अपनी योग कक्षाएं लेना, कई बार निजी सत्र सुबह 7 बजे ही शुरू हो जाता है
- दोपहर 1.30 बजेः कक्षाएं समाप्त होती हैं। घर जाकर आप अपने निजी काम कर सकते हैं
- शाम 5 बजेः शाम की कक्षाओं के लिए स्टुडियो वापस आना
- रात 9 बजेः योग कक्षाएं यहीं समाप्त और घर के लिए रवाना
- रात 11 बजेः आज का दिन खत्म होता है।

कैसे पहुंचें

एक योग प्रशिक्षक के लिए पेशेवर प्रशिक्षण अनिवार्य है। आप 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद या फिर इससे भी पहले कोर्स कर सकते हैं। एक योग प्रशिक्षक के लिए अपने कार्य में अच्छा न होना, उसके करियर के लिए सही नहीं है, इसीलिए एक अच्छे संस्थान से सही प्रशिक्षण पाठय़क्रम किया जाना जरूरी है।

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर कैसे पा सकते हैं जॉब

ये रही योग्यता के लेकर चयन की पूरी डिटेल

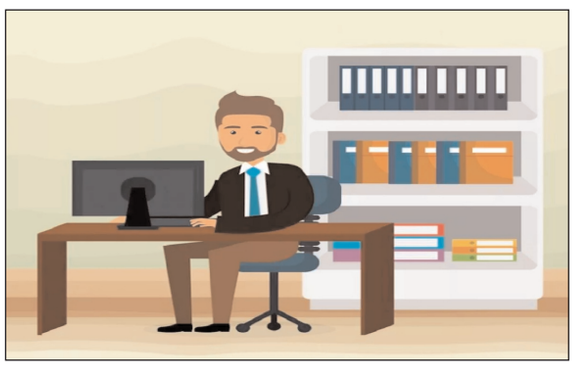

हमारे देश में सरकारी नौकरी पाने का सपना लगभग हर युवा को होता है लेकिन इसमें से कुछ लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। अगर आप भी बेहतर पद पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बीमा क्षेत्र एवं इंश्योरेंस कंपनियों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद बेहतर साबित हो सकता है। इस पद के लिए प्रतिवर्ष नौकरियां निकाली जाती रहती हैं।

एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और इसके लिए निर्धारित की गयी योग्यता, मापदंड एवं चयन प्रॉसेस की जानकारी आप यहां से चेक कर सकते हैं और इसे पढ़कर इस पद के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

इस पद पर चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन से होकर गुजरना होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 200 बहुविकल्पीय प्रकार के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा।

जो उम्मीदवार ऑनलाइन एग्जामिनेशन में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे उनको इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंत में उम्मीदवारों के द्वारा किये गए प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उनको रिक्त पदों पर तैनात किया जाएगा।

करें कैरियर से प्यार

बेशक बाहरी हालात भी उस प्रेम पर असर डालते हैं, लेकिन अंततः यह आपके विचार और भावनाएं ही हैं, जो अंतिम फैसला करती हैं, इसलिए अपने अंतर्मन के कहने पर आप क्या फैसला लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस मामले में जरूरी है कि ईमानदारी अपनाई जाए, क्योंकि बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते।

क्या अपने रोजगार से आपको प्रेम है? कुछ रुकावटें सबके सामने आती हैं, लेकिन उन्हें पार पाना असंभव नहीं होता। अपने काम के प्रति यदि आपके अंदर निराशा पैदा होती जा रही है तो नीचे बताए कुछ उपायों को एक बार अमल में लाकर देखें।

क्या आपको अपने प्रोफेशन से प्यार है? या पहले आप ऐसा सोचते थे, अब नहीं? या आप ऐसे करियर से जुड़े हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी दिल से नहीं अपना सकेंगे? अपने करियर के प्रति प्रेम आपके भीतर से ही आता है। बेशक बाहरी हालात भी उस प्रेम पर असर डालते हैं, लेकिन अंततः यह आपके विचार और भावनाएं ही हैं, जो अंतिम फैसला करती हैं, इसलिए अपने अंतर्मन के कहने पर आप क्या फैसला लेते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस मामले में जरूरी है कि ईमानदारी अपनाई जाए, क्योंकि बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने सपनों के करियर में न हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने मौजूदा कार्य को खुशी-खुशी अपना नहीं सकते। तो कैसे करेंगे आप अपने करियर से प्यार? फैसले इसलिए जरूरी होते हैं, क्योंकि वे मार्गदर्शन करते हैं। उसी मार्गदर्शन से अर्थ और कार्य के प्रति निष्ठा जागती है। यह मार्गदर्शन खुद आपकी ओर से भी आ सकता है, जब आप सोच रहे हों कि ऐसा नहीं होगा या आप किसी और के इंतजार में हों। सिर्फ इतना ही निर्णय लीजिए कि करियर को आपने फिर से अपनाना है। इससे आपको कई ऐसे विकल्पों के प्रति उन्मुक्तता मिल जाएगी, जिन्हें आप आज ही शुरू कर देंगे। जो आपका कार्य है, उसे दोनों हाथों से अपनाएं, क्योंकि प्रेम हर हालत में नफरत से बेहतर होता है। जब आप धारा के साथ बहते जाएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। प्रत्येक करियर से जुड़े कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं। खुद से इस बारे में पूछें कि आपके करियर में ऐसा क्या है? क्या आपको वह प्रोजेक्ट पसंद है, जिस पर आप काम कर रहे हैं? जो नहीं है, उससे अधिक निराश न होते हुए क्या आप धीरे-धीरे आ रहे उस परिवर्तन को अपना पा रहे हैं। अपनी प्राथमिकता में परिवर्तन लाएं और अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाएं। अपने करियर के उन पक्षों पर फोकस करें, जो कुछ लीक से हट कर हैं। एक नया परिप्रेक्ष्य नई ऊर्जा को जन्म देगा और यह नई ऊर्जा आपको आपके करियर से अधिक जुड़म्ने का मौका देगी। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हों, खुद को समझाएं कि वह कार्य असाधारण है। बेशक ऐसा न हो, लेकिन आप फिर भी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देकर कुछ नया कर दिखाएंगे। इसके विपरीत, यदि आपको अपनी मौजूदा जगह पसंद होती तो आप क्या अलग करते? कहना न होगा कि उस हालत में भी आप अच्छे कार्यों को ही अंजाम दे रहे होते। इसलिए शुरुआत अभी से कीजिए। याद रखें, यदि आपने खुद अपने ऊपर रोक न लगाई होती तो आप करियर में बहुत आगे होते।

इसका मतलब अपने कार्य पर आपकी पकड़ आपकी समझ से कहीं अधिक है। तो कब कर रहे हैं शुरुआत?

● **डेब्रा ब्राउन-वोकमैन**

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बिहार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल के सारथी बने तेजस्वी

सासाराम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ''भारत जोड़ो न्याय यात्रा'' शुक्रवार को बिहार के सासाराम जिले से फिर से शुरू हुई और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल होने के साथ कांग्रेस नेता के सारथी की भूमिका में दिखाई दिए। कांग्रेस सांसद राहुल ने रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत जमुहार में रात्रि विश्राम के बाद तेजस्वी के साथ एक लाल खुली जीप में सवार होकर यात्रा कीशुरुआत की। तेजस्वी जीप चला रहे थे वहीं कांग्रेस नेता राहुल बगल की सीट में बैठे थे। जीप में पीछे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार बैठी हुईं थीं। दोनों युवा नेताओं ने सड़क पर एकत्र भीड़ की ओर हाथ हिला कर उनका अभिवादन किया। बाद में दोनों नेता रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के टेकारी में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे और वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की।

केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका

गांधीनगर। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा की डिग्री के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन की पुष्टि करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हसमुख डी सुथार की पीठ ने 2 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुजरात के अहमदाबाद में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोनों के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के 4 दिन बाद दोनों ने पिछले साल सितंबर में उच्च न्यायालय का रुख किया था। अपील में इस मुद्दे को भी उठाया गया है कि शिकायत का बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ रहा है।

दरवाजा हमेशा खुला है, नीतीश आएंगे तो देखेंगे: लालू यादव

पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। शुक्रवार की सुबह वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैशाली के जंदाहा पहुंचे। जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार को दोबारा मौका देने की बात पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा खुला है, जब आएंगे तो देखेंगे। अब लालू यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ सकती है। आरजेडी सुप्रीमो ने इस दौरान किसान आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। लालू यादव के दिए गए इस नए बयान के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि राजद के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं हुए हैं।

कांग्रेस के खाते फ्रीज मामले में कुमारस्वामी का पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बताया कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपये की रिकवरी का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही क्राउडफंडिंग से जुटाए गए राशि को भी हमारी पहुंच से दूर कर दिया गया है। अजय माकन के इस बयान पर कुमारस्वामी ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर कुछ भी गलत होता है या उनके अकाउंट के साथ किसी भी प्रकार से कोई अवैध गतिविधि हुई है तो वे कभी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है? उन्हें उन विशेष एजेंसियों से पूछना होगा जो उनके खातों का हिसाब रखती है। माकन के बयान पर भाजपा नेता सीएन आश्वत नारायण ने कहा, देश का कानून हम सब पर लागू होता है। यदि इसमें कोई उल्लंघन होता है तो इसका परिणाम भुगतना होगा।

पार्थ चटर्जी के करीबियों के आवास पर ईडी की छापेमारी

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगियों के आवास पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला के तहत की जा रही है। साल 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पार्थ की गिरफ्तारी उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21 करोड़ नकद और करीबन एक करोड़ से अधिक के आभूषण बरामद होने के बाद हुई थी। सूत्र ने कहा, ईडी राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री के करीबी के आवास पर छापेमारी कर रही है। शिक्षक भर्ती घोटाला के तहत यह छापेमारी जारी है। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकारी नौकरियों की बिक्री का नेक्सस बहुत सक्रिय है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी शेयर की।

जो कभी नहीं चाहते थे राम मंदिर बने वो भी अब श्रीराम बोलने लगे हैं : मोदी

रेवाड़ी (हरियाणा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी के गांव माजरा में पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9750 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रेवाड़ी से रिश्ता कुछ अलग ही रहा। कहा कि मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र राव इंद्रजीत सिंह ने जैसे बताया सीएम मनोहर लाल ने जैसे बताया कि 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम उम्मीदवार घोषित किया था तब मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। तब रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था जो सिद्धि बन गया था। मैं फिर रेवाड़ी आया हूं तो अबकी बार एनडीए सरकार 400 पार।

पीएम ने कहा कि साथियों लोकतंत्र में सीटों का महत्व है लेकिन मेरे लिए जनता का अशीर्वाद बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो ये आप सब के आशीर्वाद के कारण। उन्होंने कहा कि मैं कल ही दो देशों की यात्रा के बाद देर रात हिन्दुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है। हर कोने से भारत को शुभकामना मिलती है वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, हर भारतीय का है। आप सबका है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जी 20 का सफल सम्मेलन आपके आशीर्वाद से हुआ। तिरंगा चंद्रमा पर पहुंचा, जहां कोई नहीं पहुंच सका। कहा कि यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ। पीएम ने कहा कि 10 वर्ष में भारत 11वें नंबर से उठकर पांचवे नंबर की

आर्थिक महाशक्ति बना है। अब मुझे अपने तीसरे टर्म में और आने वाले वर्षों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें, रेलवे का आधुनिक नेटवर्क, बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का मुझे अवसर मिला है।

मोदी ने कहा कि म्यूजियम में गीता संदेश कुरुक्षेत्र जैसी पावन धरा से दुनिया को परिचित कराएगा। उन्होंने कहा कि आजकल देश-दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। कहा कि यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटी दी थी। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो आज पूरा देश रामलला के दर्शन कर रहा है।

देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है और तो और तो कांग्रेस के लोग जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम का मंदिर बने वह भी अब जय सियाराम बोलने लगे हैं।

कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से रोड़े अटकाए थे, मैंने गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाके रूहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद अनुच्छेद 370 इतिहास में खो गया है।

पीएम ने कहा कि यहीं रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की धरा से लिया गया वह संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरपी के तहत पूर्व सैनिकों को करीब एक लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के पूर्व सैनिक रहेंगे। सिर्फ रेवाड़ी के पूर्व सैनिकों की बात करूं तो उन्हें 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए जितना प्यार रेवाड़ी को मिला है उससे कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए रखा था। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को नकार दिया है।

पीएम ने कहा कि देश का 22वां एम्स बन रहा है, 10 साल में 15 नए एम्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। वहीं, हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कालेज बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि पहले रेल के विकास के लिए हर वर्ष औसत 300 करोड़ बजट मिलता था। इस वर्ष रेलवे के लिए करीब 3000 करोड़ का बजट रखा गया है। रोहतक-महम-हांसी-जींद सोनीपत जैसी नई रेल लाइनों और अंबाला कैंट रेल लाइनों की दोहरीकरण से लाखों लोगों को फायदा होगा। ऐसी सुविधाओं से जीवन और कारोबार आसान होता है।

खड़गे ने मोदी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप

कहां हैं दो करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपये?

पटना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि उसने वादे के मुताबिक नौकरियां नहीं दी हैं और उसके शासन में देश की कर्ज की स्थिति खराब हो गई है। खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के औरंगाबाद में एक सार्वजनिक रैली में पूछा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कहां हैं दो करोड़ नौकरियां? कहां है मोदी की गारंटी? वह 15 लाख रुपये कहां हैं जिसका उन्होंने वादा किया था?

अपना हमला जारी रखते हुए खड़गे ने कहा कि या तो प्रधान मंत्री झूठे हैं या आप लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं सभी को 15 लाख रुपये दूंगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं मिला... यूपीए के समय सरकार केवल कर्ज में थी 55 लाख करोड़ रुपये, लेकिन मोदी काल में हम पर 185 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी न तो संविधान को मानती है और न ही लोकतंत्र को। उन्होंने कहा कि वे (भाजपा) तानाशाही चाहते हैं। इसलिए हमें खुद को मजबूत करके इनसे लड़ने की जरूरत है।

खड़गे ने एनडीए में जाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने न्याय यात्रा का समर्थन किया, खासकर यहां मौजूद लोगों की संख्या देखकर मुझे विश्वास है कि इस बार यहां से कांग्रेस की जीत होने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वह मर जायेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जायेंगे और आज वह डर के कारण बीजेपी के साथ हैं. असली नेता राहुल गांधी हैं, जो

सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी का राज्य में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का इतिहास रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर न्याय की इस बड़ी लड़ाई को जीतेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय के अगले कदम के रूप में जाति जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और कंप्यूटर क्रांति जैसे कई क्रांतिकारी कार्य किये हैं। इसी तरह हम एक और क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो है जाति जनगणना। सामाजिक न्याय के लिए अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस यह करेगी।

कांग्रेस ने बहुदलीय प्रणाली को बचाने के लिए न्यायपालिका से की अपील

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को न्यायपालिका से भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाने की अपील की। आयकर विभाग द्वारा सबसे पुरानी पार्टी के बैंक खातों को कथित तौर पर फ्रीज करने के बाद कांग्रेस प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर, मोदी सरकार ने लोक सभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस - के Accounts Frozen कर दिए है। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउडफंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है, उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे ! उन्होंन लिखा कि हम न्यायपालिका से अपील करते हैं, कि इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सडकों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरह से लड़ेंगे।

राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने खुलासा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उनके अनुसार, गुरुवार को सूचना मिली थी कि बैंक पार्टी द्वारा जारी चेक का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। आगे की जांच करने पर पता चला कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 500 विकेट

राजकोट। अनुभवी स्पिनर आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 98 टेस्ट खेले हैं। वह शुक्रवार (16 फरवरी) को राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के दौरान 500 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंते। जैक क्रॉली टेस्ट क्रिकेट में आर अश्विन का 500वां शिकार बने।

साथ ही, अश्विन दिग्गज अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उनके नाम 619 विकेट हैं। 37 वर्षीय अश्विन श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद 100 से कम टेस्ट में 500 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। मुरली ने केवल 87 मैचों में 500 विकेट तक पहुंचे थे। अश्विन 50, 100, 150, 200, 350, 400, 450 और 500 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय हैं, वहीं 250 और 300 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले दुनिया में सबसे तेज भारतीय हैं। मुथैया मुरलीधरन रेड-बॉल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 133 मैचों में मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं। मुरलीधरन के बाद शेन वार्न, जेम्स एंडरसन, अनिल कुंबले और स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम आता है।

खबर लिखे जाने तक दूसरे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने भारत के पहले पारी में 445 रन के जवाब में 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। शतकवीर डेन डकेट 133 और जो रूट 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इसके पहले भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 131, रवींद्र जडेजा ने 112 और सरफराज खान ने 62 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 4 विकेट झटके।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 376 चढ़ा तो निफ्टी 22 हजार के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई जिससे बाजार चढ़कर बंद हुआ। इंडेक्स में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एलएंडटी, इन्फोसिस और महिंद्रा एंड महीना के शेयर में उछाल से बाजार बढ़कर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 376.26 अंक या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 72,426.64 पर बंद हुआ। इंट्राडे कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 72,545.33 के उच्च और 72,218.10 के निचले स्तर तक चला गया था। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 129.95 अंक या 0.59 प्रतिशत चढ़कर एक बार फिर 22 हजार के लेवल को पार करते हुए 22,040.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में विप्रो का शेयर 4.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे ज्यादा लाभ में रहा।

रक्षा मंत्रालय ने 29 हजार करोड़ के सौदों को दी मंजूरी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए नौ मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट और भारतीय तटरक्षक बल के लिए छह पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत 15 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। साथ ही सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाए जाएंगे। यह सौदा कुल 29 हजार करोड़ रुपये का होगा। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने कानपुर स्थित एक कंपनी से 1752.13 करोड़ रुपये के सौदे का भी करार किया है। इस सौदे के तहत 463, 12.7 एमएम की रिमोट कंट्रोल गन का निर्माण किया जाएगा। ये गन भी नौसेना और तटरक्षक बल के जवानों को मिलेंगी। रक्षा मंत्रालय के इन सौदों से ना सिर्फ भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होगा बल्कि इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा।

अब पीएसएस के तहत कर्नाटक कर सकेगा चना की खरीद

नई दिल्ली। केंद्र ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 2023-24 रबी सीजन में कर्नाटक से 1.39 लाख टन चना खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इसकी जानकारी दी। मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी की है। करंदलाजे ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने 5,440 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर पीएसएस के तहत मंजूरी दी है। राज्य को आरकेवीवाई योजना के तहत धनराशि जारी करने के संबंध में, उन्होंने कहा कि 235.14 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त का उपयोग कर्नाटक सरकार द्वारा आरकेवीवाई योजना के तहत आठ घटकों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। मंत्री शोभा ने कहा कि स्वीकृत राशि का उपयोग गोदामों के निर्माण, जल संचयन संरचनाओं, ट्रैक्टरों, पावर टिलर और ड्रोन की खरीद आदि के लिए किया जाएगा।

बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है नई पल्सर बाइक

नईदिल्ली। बजाज ऑटो अपनी नई पल्सर बाइक को बाजार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। उम्मीद यह जाहिर की जा रही है कि उसकी पल्सर का नया मॉडल एनएस200 का अपडेटेड वेरिएंट होगा। बाजार में उतारने से पहले बजाज ऑटो ने अपनी नई बाइक का वीडियो टीजर जारी किया है। इसे देखने के बाद पता चलता है कि नई पल्सर बाइक में इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल और एलईडी हेडलैंप के साथ हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिल सकता है। हालांकि, पिछली पल्सर एनएस 200 में हैलोजन हेडलाइट सेटअप था। नई एलईडी लाइटिंग एनएस 200 को आधुनिक बनाएगी। बजाज पल्सर एनएस200 का मॉजूदा मॉडल दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड 2023 में आती है। भारत के एक्स-शोरूम में इसकी कीमत करीब 1.41 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 1.49 लाख रुपये तक जाती है।

भारत-कतर : सधी हुई ऊर्जा कूटनीति

अरविंद कुमार मिश्रा

बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अनुमान है कि देश में प्राथमिक ऊर्जा मांग 2050 तक दोगुनी हो जाएगी। भारत की मौजूदा आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत से अधिक है। आर्थिक तरक्की को गति देने और समावेशी विकास के लिए ऊर्जा की नई साझेदारियां विकसित करनी होंगी। इस दिशा में भारत ने कतर के साथ 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात का समझौता किया है। 78 अरब डॉलर का यह समझौता ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्णायक हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयातक कंपनी पेट्रोनेट लि. हर साल 75 लाख टन गैस खरीदेगी।

प्राकृतिक गैस की मदद से देश में बिजली, उर्वरक और सीएनजी की उपलब्धता टिकाऊ होगी। देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 35 हजार किलोमीटर लंबी %वन नेशन-वन गैस ग्रिड% स्थापित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक पीएनजी और एलएनजी की उपलब्धता आसान बनाना है। हमारी ऊर्जा जरूरतों में अभी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत है। इस दशक के अंत तक इसे 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। प्राकृतिक गैस शून्य कार्बन उत्सर्जन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगी। इस समझौते से वर्तमान भाव पर भारत को 0.8 डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बचत होगी, जिससे 2048 तक देश को छह अरब डॉलर का लाभ होगा। साथ ही, भारत के एलएनजी आयात में कतर की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगी। प्राकृतिक गैस आयात को लेकर इससे पहले

दोनों देशों के बीच 1999 में समझौता हुआ था, जो 2028 में समाप्त होगा। अमेरिका के बाद कतर एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी अपनी क्षमता को 2027 तक बढ़ाकर 12.6 टन सालाना करेगी।

भारत और कतर गैस समझौता देश की सधी हुई ऊर्जा कूटनीति का परिणाम है। अभी हम अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करते हैं। प्राकृतिक गैस के मामले में यह अनुपात लगभग 56 प्रतिशत है। तेल और गैस के लिए खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता अधिक रही है। इससे हमें ओपेक की मनमानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए पिछले वर्ष भारत ने सबसे अधिक कच्चे तेल की खरीदारी रूस से की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वर्ष देश ने रूस से प्रतिदिन 16.6 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीदारी की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत परिशोधित (रिफाइंड) पेट्रोलियम उत्पादों का न सिर्फ बड़ा केंद्र बना, बल्कि यूरोप को सस्ती दर पर परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया। इससे ऊर्जा क्षेत्र के बड़े बाजार में भारत की मौजूदगी बढ़ने से ओपेक की मनमानी घटेगी।

पिछले दिनों गोवा में आयोजित ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत की ऊर्जा विविधिकरण को दुनिया ने देखा। इस दौरान भारत-कतर गैस समझौते के साथ ही भारतीय कंपनियों ने कई नवाचार पेश किए। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्वदेशी अल्कलाइन (क्षारीय) इलेक्ट्रोलाइजर पेश किया, जो दुनिया में सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर है। भाभा परमाणु शोध संस्थान के सहयोग से इसका प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस प्रौद्योगिकी से औद्योगिक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव है। भारत ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ओएनजीसी द्वारा तैयार समुद्री सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। समुद्र में तेल एवं गैस परियोजनाएं सबसे जटिल अवसंरचना होती हैं। तेल और गैस उत्खनन तथा परिशोधन के दौरान जोखिम अधिक होता है। यहां मानव निर्मित हादसों के अलावा मौसमी बदलाव का खतरा बना रहता है। ऐसे में मानव जनित तथा प्राकृतिक हादसों का प्रभाव कम करने के लिए ओएनजीसी ने समुद्री सर्वाइवल सेंटर स्थापित किया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों की बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री साय का विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास पर है विशेष जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में तैयार किये गये बजट में विशेष पिछड़ी जनजाति के सदस्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस बजट प्रावधान से छत्तीसगढ़ में रह रहे बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार और अबूझमाड़िया लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। घास-फूस के घरों की जगह वे पक्के घरों में रह सकेंगे।

पेयजल की अच्छी सुविधा होगी। अभी अधिकांश विशेष पिछड़ी जनजाति की बस्तियों में पानी दूर से लाना होता है। कई बार इस जनजातीय समुदाय के लोग झिरिया आदि से पानी पीते हैं। अशुद्ध पेयजल की वजह से बीमारियां पनपती हैं।

देश में पहली बार इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई गई। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में इस योजना पर तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस पर सीधी नजर रख रहे हैं। बीते माह मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले में बिरहोर बस्तियों का दौरा भी किया। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने इन बस्तियों में रहने वाले लोगों से संवाद भी किया। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते रहे, इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध हो जाने से अब इन इलाकों में तेजी से विकास हो सकेगा। यह योजना इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि इन जनजातियों का भौगोलिक परिवेश बहुत कठिन है। जहां पर बस्तियां बसी हैं वहां तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा पाना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं दे पाना चुनौती होती थी लेकिन मुख्यमंत्री श्री साय के दृढ़ संकल्प के आगे रास्ता आसान हो गया है।

जनमन योजना के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं अपितु इनके लिए रोजगार के अवसर भी इसके माध्यम से सृजित किये जा रहे हैं। सरगुजा और बस्तर की ओर फोकस की सरकार की नीति भी इन अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काफी उपयोगी होगी। स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इन जनजातियों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा। इन योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जनमन मित्र तथा सखी विशेष रूप से उपयोगी साबित हुए हैं। वे घर-घर जाते हैं पीवीटीजी से उनकी भाषा में बात करते हैं। सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं और फार्म भी भरवाते हैं। इसके बाद वे प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय से इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को देना सुनिश्चित कराते हैं।

कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना मोदी सरकार की तानाशाही: बैज

रायपुर. केंद्र द्वारा कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने तानाशाही बताते हुये कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों की लोकतांत्रिक गतिविधियों और सांगठनिक गतिविधियों पर तानाशाहीपूर्वक रोक लगाना चाहती है, इसीलिये बिना किसी वैध कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करके एक अभूतपूर्व और क्रूर कदम उठाया है। यह कदम लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जिससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना, जिसमें क्राउड फंडिंग अभियान से जुड़े खाते भी शामिल है, न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वित्तीय स्थिरता पर हमला है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी एक जबरदस्त हमला है।

बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए कार्ययोजना बनाकर करेंगे काम: गृहमंत्री

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्ययोजना और प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुदूर वनांचल के गांवों तक सभी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, इसलिए सरकार ने बस्तर के कोने-कोने तक विकास की गंगा पहुंचाने का फैसला लिया है. जहां-जहां भी कैम्प खुलेंगे वहां विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जाएगा. 11 कैम्प पूर्णत: स्थापित हो चुका है, उसके आसपास योजना का फायदा मिलेगा. विकास के लिए हर स्तर पर चर्चा और वार्ता के लिए विष्णुदेव सरकार तैयार है. विकास के लिए जो भी बाधा होगी, उसे हटाएंगे.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के सुदूर अंचल में व्यक्ति बीमार होता है, तो बेहतर इलाज की अपेक्षा होती है. साथ ही साथ शिक्षा गांव तक पहुंचे. हर गांव में यह चाहते कि रात में लाइट जलनी चाहिए. जो सुविधाएं शहर में होती है, वह सुदूर वनांचल बस्तर के गांव में पहुंचनी चाहिए. यह बस्तर के लोग चाहते हैं. मैं लोगों से मिलकर आया हूं. इसलिए योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा. नक्सलियों के एक्टिव होने और केंद्र से एक्सट्रा फोर्स मांगने पर कहा गृह मंत्री ने कहा कि अमित शाह का आना हुआ था, उन्होंने कार्ययोजना बना रखी है. चर्चा जो क्यों उनकी विकास को रोका जाए, बस्तर के गांव में पहुंचने वाले विकास को क्यों रोका जाए. विजय शर्मा ने कहा कि विष्णु देव सरकार ने निर्णय लिया है, बस्तर के कोने-कोने तक विकास पहुंचेगी. इसलिए योजना लाई गई है. इस योजना में जहां भी कैंप लगेगा, वहां चाहे करें, वार्ता जो चाहे करें. बस्तर की विकास की चिंता जिसको भी है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं. जो अधिकार है, वनांचल के लोगों को संरक्षित करते हुए होगा. लेकिन विकास होगा. विकास की गंगा बहेगी, और जो भी अवरोध होगा जो भी बाधक होंगे उन सारी बढ़ाओ को नक्सली अपने आप को मजबूती मजबूत करने की वाले सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव कहां तक पहुंचने चाहिए. जिन सरकारों ने नहीं किया, उनका जवाब जनता दिया है. अभी विष्णु देव सरकार है. विकास की गंगा कोने-कोने तक तक पहुंचेगी.

1 साल के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी

■ स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित प्रमोशन का मुद्दा पर मंत्री अग्रवाल ने बताया
■ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लंबित प्रमोशन का मुद्दा सदन में गूंजा। विधायक रिकेश सेन के स्थान पर अनुज शर्मा ने प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे स्कूल संचालित होने और शिक्षकों का प्रमोशन नहीं होने का मुद्दा उठाया। जवाब में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि 1 साल के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। मंत्री के जवाब पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि आप सक्षम मंत्री हैं, ऐसे में एक साल का समय क्यों ले रहे हैं, छह महीने के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण कराये।

विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश सर्वोपरी है, आपके आदेश के अनुरूप छह महीने के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया को बाधित करके रखा गया था। प्रदेश में अभी भी ढाई लाख शिक्षक हैं, जिनका प्रमोशन अभी ड्यू है। वहीं जहां तक प्रभार का सवाल है, तो ये परंपरा पुरानी है, जब स्कूल के सीनियर को प्राचार्य का प्रभार दे दिया जाता था। शिक्षा मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि अभी तक की प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान सदन में किया गया है। विभाग ने 33000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। 1 साल के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

इस बार गर्मी में 65 सौ मेगावाट बिजली खपत का अनुमान

गर्मी की आहट सुनते ही चढ़ा बिजली का पारा

रायपुर। गर्मी का अभी आगाज नहीं हुआ है. लेकिन बिजली की खपत में जरूर गर्मी के तेवर नजर आने लगे है. फरवरी में ही खपत 5 हजार मेगावॉट को पार कर चुका है.

प्रदेश में जहां तक बिजली उत्पादन का सवाल है. तो छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर उत्पादन कंपनी के संयंत्रों में इस समय 23 सौ मेगावाट का ही उत्पादन हो रहा है. ऐसे में बिजली की पूर्ति करने के लिए सेंट्रल सेक्टर का सहारा लिया जा रहा है. इस बार गर्मी के प्रकोप और प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए खपत 65 सौ मेगावाट तक पहुंच सकती है. पिछली बार अधिकतम खपत 62 सौ मेगावाट तक हुई थी.

सीएसपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज खरे ने बताया कि पहले कभी बिजली खपत में इतनी लोड नहीं बढ़ती थी, लेकिन इस बार खपत अधिक हो रही है. सुबह 6 से 9 बजे तक डिमांड ज्यादा बढ़ रही है. इसके पीछे गर्मी के मौसम में किसानों का धान की फसल लेना है, जिससे लोड अधिक आ रहा है. ऐसे में सेंट्रल सेक्टर से हमेशा सहारा रहता है. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कोई खुद की बिजली नहीं होती, वह हमेशा दूसरो लेती है. छत्तीसगढ़ में अप्रैल और मई माह में बिजली की काफी डिमांड होती है, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है.

असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सहित अनेक पदाधिकारी भाजपा में शामिल

रायपुर। असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पाण्डेय सहित सैकड़ो पदाधिकारियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, सांसद सुनील सोनी, विधायक अमर चंद्राकर, अनुज शर्मा, नरेश गुप्ता, शिवरतन शर्मा, महेश गागड़ा मौजूद

रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंत्री विद्यायक अजय चंद्राकर ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में लो निरंतर शामिल हो रहे है। शामिल होने वालों में प्रमुख रूप से जीतेश शर्मा जिला अध्यक्ष केसीसी, पंकज तिवारी जिला अध्यक्ष राजनांदगांव केसीसी, विपिन तिवारी प्रदेश संयोजक फुटकर व्यापारी संघ, सौरभ निर्वाणी, राजीव अवस्थी, श्रीमती रेख सिंह, डामेश्वर साहू, प्रेमकुमार सिंह , सुमन वर्मा, प्रकाश शर्मा, संदीप पाण्डेय, सत्यनारायण शर्मा, राहुल वर्मा, नीरज ठाकुर, अग्निवेश शर्मा, आदि शामिल है। अनुप केशव चंद्राकर, निशांत शर्मा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

फूल बेचने वाले ने 60 लाख, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 2.90 करोड सरेंडर किया टैक्स

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार के गठन के बाद राज्य का जीएसटी विभाग टैक्स चोरों पर धावा बोल दिया है। प्रदेश में लगातार छापे डाले जा रहे हैं और इसमें लाख से लेकर करोड़ तक में रकम सरेंडर किए जा रहे हैं। जीएसटी विभाग के अफसरों ने बताया कि टैक्स चोरी रोकने के लिए इन्फोर्समेंट विंग में नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। विंग द्वारा लगातार न केवल व्यवसाय स्थलों की जांच की जा रही है बल्कि राज्य में सभी प्रमुख मार्गों पर ई वे बिल की भी जांच की जा रही है। इसी दौरान ई-वे बिल की जांच से दो वाहनो से 24 लाख रु वसूल किया गया है। इसमें चार वाहनो को जब्त कर आगे कार्यवाही की जा रही है। जिन वाहनो से टैक्स और पेनाल्टी वसूल किया गया है उनमे कोयला और एमएस वायर बिना ई वे बिल के ले जाया रहा था। बोगस फर्म बनाकर उनके नाम से माल परिवाहित करने वालों पर विभाग की विशेष नजर है। विभाग ने इस बार अपनी रणनीति बदली है और फॉरवर्ड बैकवर्ड एनालिसिस करते हुए परिवहित माल के स्त्रोत तक भी पंहुच कर कार्यवाही की जा रही है। ई-वे बिल के आधार पर कार्यवाही करते हुये इन्फोर्समेंट विंग ने रायपुर के रूप लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। स्टॉक में गड़बड़ी पाये जाने पर संचालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुये 50 लाख रुपए टैक्स मौके पर ही सरेंडर किए।

बिना टेंडर के कोटेशन पर लाखों की दवा खरीदी का मामला उठा

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में घोषणा की कि तीन लाख तक दवा खरीदी सीएमएचओ बिना टेंडर के कोटेशन लेकर 15 मिनट में कर सकते हैं। वे कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू के प्रश्न पर जवाब दे रहे थे। साहू ने प्रश्न काल में सक्ती जिले में डॉक्टरों द्वारा बिना टेंडर के कोटेशन पर लाखों की दवा खरीदी का मामला उठाया था। उन्होंने पूछा कि क्या कोटेशन लेकर दवा खरीदी के नियम हैं। साहू ने वर्ष 21-22 से 23-24 तक इस तरह की जानकारी मांगी। मंत्री जायसवाल ने कहा कि पूरी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्रों में दे दी गई है। फिर भी दवा खरीदी के लिए तीन तरह की व्यवस्था है। यह कि 50 हजार तक की खरीदी सिंगल कोटेशन पर, 3 लाख तक तीन फर्मों से कोटेशन लेकर उसमें न्यूनतम दर पर और 3 लाख से अधिक की खरीदी टेंडर बुलाकर ही की जा सकती है। बालेश्वर ने कहा कि इलाज जैसे संवेदनशील व्यवस्था के लिए 2-3 लाख तक की खरीदी के अधिकार सीएमएचओ को दे दें। मंत्री जायसवाल ने कहा कि 3 लाख तक की खरीदी तीन दुकानों से कोटेशन लेकर सीएमएचओ 15 मिनट में कर सकता है। साहू ने जैजेपुर उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की धीमी गति पर ध्यानाकृष्ठ कराते हुए सरवरी, ठठारी, सेंदरा और मांदरी को लिए स्वास्थ्य केंद्र की मांग रखी। मंत्री ने परीक्षण करवा लेने का

भारत बंद-लगातार किसानों की मांगों को टालती रही सरकार: कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उधोराम साहू और रायपुर नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दूबे ने संयुक्त प्रेस कांग्रेस ली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने किसानों के भारत बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की लेकिन आज दो साल में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई. उधोराम साहू ने कहा कि जिस तरह से पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं. इससे पहले भी साढ़े सात सौ किसानों को आहुति देनी पड़ी थी. केंद्र सरकार लगातार उनकी मांगों को टालती रही. आज भारत बंद का आह्वान किया गया है. कांग्रेस इसका समर्थन करती है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंबिकापुर में केंद्र में सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी कानून बनाने की गारंटी दी है. कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने कहा हमारा किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा समर्थन है. सात सौ से अधिक किसानों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों से बात की. एक कमेटी गठित की लेकिन आज दो साल बीत गए इसकी एक बैठक तक नहीं हुई. सरकार देश में अलग-अलग फसल लेते हैं. मौसम आधारित खेती है, इसके बाद भी किसानों को कोई समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है.

रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त

रायपुर। कलेक्टर श्री चंदन कुमार के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में बीते 15 फरवरी को जिला खनिज टास्क फोर्स ने कई इलाकों में दबिश देकर रेत के अवैध खनन में लगे चैन माउण्टेड मशीन और वाहन जब्त किए। जिला खनिज टॉस्क फोर्स में राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। टॉस्क फोर्स ने रेत, मुरुम, चूनापत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न 51 वाहनों और 6 चैन माउण्टेड मशीनों को जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार बलौदाबाजार ने खनिज रेत के अवैध परिवहन कर रहे 22 वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम दतान (ख) में रात्रि में रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 2 चैन माउन्टेड मशीन एवं 3 हाईवा को नदी में रेत भराई के दौरान जब्त किया। इसी प्रकार कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम भदरा में रात्रि में रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 3 चैन माउन्टेड मशीन को तथा ग्राम भदरा एवं सिनोधा में रेत से भरी 8 हाईवा को जब्त कर कसडोल थाने के सुपर्द किया गया है।

मंदिर की सीढ़ियों पर लगे स्क्रीन पर चला अश्लील वीडियो, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप

डोंगरगढ़। विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां आज देर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर लगे एलईडी टीवी में अश्लील वीडियो दिखने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया. एलईडी स्क्रीन पर चल रहे अश्लील वीडियो को कई श्रध्दालुओ ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया. जिसके बाद पूरा मामला डोंगरगढ़ थाने पहुंचा. छत्तीसगढ़ की आराध्य माता बमलेश्वरी मंदिर जो की पहाड़ो पर स्थित है. जहां पहुंचने के लिये श्रद्धालुओं को लगभग ग्यारह सौ सीढ़ियां चढ़ना होता है. वहीं सीढ़ियों के किनारे कई जगह मंदिर ट्रस्ट द्वारा एलईडी स्क्रीन लगाई गई है. जिसमें शुक्रवार देर शाम अश्लील वीडियो चलते दिखने से श्रद्धालुओं में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई. कई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ एलईडी स्क्रीन के सामने थे और मंदिर परिसर में अश्लील वीडियो चलने से अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे. जिसके बाद कुछ श्रद्धालुओं ने पूरे मामले के शिकायत डोंगरगढ़ थाने पहुंच कर की. दुर्ग के रहने वाले वरुण जोशी बताते है कि वे डोंगरगढ़ माता मंदिर हमेशा परिवार के साथ आते रहते है इसबार भी वे डोंगरगढ़ माता के दर्शन को पहुंचे थे. लेकिन जब दर्शन करके उतर रहे थे तब उन्होंने अश्लील वीडियो स्क्रीन पर चलता देखा उस समय वहां पर सैंकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ महिलाएं भी मौजूद थी.

पीडब्ल्यूडी के लिए 8016 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे पारित

प्रदेश में बेहतर होगा सड़कों का ढ़ांचा, नई सड़कों और फ्लाईओवर सहित कई प्रस्ताव

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री अरुण साव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रुपए अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई जिसे आज विधानसभा में पारित किया गया। श्री साव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ी है। इससे यातायात पर दबाव बढ़ा है। सड़कों के चौड़ीकरण की जरूरत है और इनके सुदृढ़ीकरण की जरूरत भी है ताकि यातायात व्यवस्थित हो, इस जरूरत के अनुरूप बजट प्रावधान किये गये हैं।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप वर्ष 2027 तक प्रत्येक राजमार्ग को बारहमासी एवं यातायात की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य के सभी राज्यमार्गों को यथासंभव डबल लेन किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि पहुंचविहीन गांवों में सड़क अधोसंरचना सुनिश्चित करेंगे ताकि ये गांव मुख्यधारा से जुड़ सकें। श्री साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में पूरी तरह गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी दृष्टि एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से निरीक्षणकर्ता अधिकारी कार्यस्थल से ही कार्य के फोटोग्राफ लेकर सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। श्री साव ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ रुपए रखे गये हैं। प्रदेश में नये रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज एवं अंडर पास बनाये जाएंगे।

पंडरी-मोवा मार्ग पर बनेगा फ्लाईओवर- 75 करोड़ रुपए की लागत से पंडरी मोवा मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। तेलघानी नाका चौक से स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 7 तक अंडर पास का निर्माण किया जाएगा, इसकी लागत 10 करोड़ होगी। मंदिरहसौद स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज बनेगा, इसकी लागत 12 करोड़ रुपए होगी। रायगढ़ चक्रधर नगर में रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा जिसकी लागत 80 करोड़ रुपए होगी। अटल पथ एक्सप्रेस वे में फुंडहर चौक सेप्रेटर बनाया जाएगा जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए होगी। बिलासपुर में मंगला चौक में 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ग्रेट सेप्रेटर बनाया जाएगा। रिंगरोड क्रमांक 2 रायपुर जरवाय मार्ग पर 20 करोड़ रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। सरोना चौक रिंगरोड क्रमांक 1 पर 10 करोड़ रुपए की लागत से ओवरपास बनाया जाएगा। भारत माता चौक से कुकरी तालाब के पास स्टेशन प्लेटफार्म 7 तक ओवरपास तथा अंडरपास बनाया जाएगा, इसकी लागत 5 करोड़ रुपए होगी।

महतारी वंदन योजना, अब तक 62 लाख से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन

रायपुर। प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 05 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है। इस योजना के तहत अब तक 62 लाख 15 हजार 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 15 फरवरी को एक दिन में ही 02 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 62 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.